

तरुण छत्तीसगढ़

आम आदमी का अपना दैनिक अखबार

E-mail:
tarunpressraipur@gmail.com
tarun_press@yahoo.co.in

Web:
www.tarunchhattisgarh.in
facebook.TarunChhattisgarh
phone: 0771-2543112

■ रायपुर,शुक्रवार 27 नवंबर 2026 ■ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष-3 ■ वर्ष -42 ■ अंक-237 ■ पृष्ठ 8 ■ डाक संस्करण 28 नवंबर 2026 ■ मूल्य-2.00 रुपये

रामायण फिल्म की कहानी पसंद नहीं तो अपनी फिल्म बना लीजिए:सुको

नई दिल्ली,27 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर कपूर अभिनीत हिंदी फिल्म 'रामायण' को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि फिल्म में महाकाव्य रामायण को विकृत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है और निर्माताओं ने अपनी समझ के आधार पर महाकाव्य को प्रस्तुत किया है। अदालत ने टिप्पणी की कि जिन लोगों की रामायण को लेकर अलग व्याख्या है, वे अपनी फिल्म बना सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने वकील को अपना समय बर्बाद न करने की चेतावनी भी दी।

कांग्रेस ने सांसदों को 29 तक दिल्ली बुलाया

रायपुर,27 नवंबर। संसद के आगामी विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपने सांसदों को अलर्ट कर दिया है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ समेत देशभर के सांसदों के लिए व्हिप जारी करते हुए 29 नवंबर तक दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस प्रभारी और सांसद सुखदेव भगत ने छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों को भी अनिवार्य रूप से दिल्ली पहुंचने कहा है। संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2026 तक प्रस्तावित है। लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर से शुरू होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि दोनों सदनों में जरूरी सरकारी कामकाज किया जाएगा और जरूरत के मुताबिक कार्यवाही 3 दिसंबर तक चल सकती है। इस विशेष सत्र को लेकर परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर भी सियासी चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इन मुद्दों से जुड़े विधायी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की नई कोशिश कर सकती है। कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। 27 नवंबर को शाम 4:30 बजे दिल्ली में कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक होगी।

महादेव सट्टा एप: ईडी का रायपुर-भिलाई समेत कई जिलों में छापा

■ तरुण छत्तीसगढ़

रायपुर,27 नवंबर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर, दुर्ग-भिलाई और धमतरी समेत कई जिलों में दबिश दी है। शुक्रवार को ईडी की अलग-अलग टीमों ने कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई महादेव ऑनलाइन बेटिंग और सट्टा ऐप से जुड़े मामले में की जा रही है। जानकारी के अनुसार, रायपुर के जोरा स्थित पार्क शिरीन कॉलोनी में ईडी की टीम ने जेल एवं होमगार्ड विभाग में वित्त सहायक के पद पर पदस्थ राजेन्द्र सिंह के घर दबिश दी है। टीम यहां दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की जांच कर रही है। वहीं, दुर्ग-भिलाई में एक चर्चित होटल के मालिक के घर और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा धमतरी में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर के एक



रिश्तेदार के घर समेत अन्य ठिकानों पर भी जांच एजेंसी की टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय लेनदेन की जांच के सिलसिले में की जा रही है। फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई जारी है। जांच एजेंसी की ओर से अब तक इस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में ईडी ने दिल्ली के लग्जरी कैटरर राहुल मक्कर, रियल एस्टेट कारोबारी शेली ग्रोवर और उनके बेटे माधव ग्रोवर से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की है। जांच के दायरे में पिता-बेटे की 9 कंपनियां भी हैं। राहुल मक्कर ने सौरभ चंद्राकर की दुबई में हुई शाही शादी में कैटरिंग का काम किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शक है कि महादेव सट्टे से कमाए गए करोड़ों रुपए इन लोगों तक पहुंचाए गए। इस रकम को दुबई के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और भारत के हॉस्पिटैलिटी कारोबार में निवेश किए जाने की आशंका है। यह कार्रवाई सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर की गई। ईडी अब पता लगा रही है कि सट्टे से कमाए गए पैसे किन लोगों और कंपनियों के जरिए आगे भेजे गए और उनका इस्तेमाल कहां किया गया।

परिसीमन से बढ़ेगा जनप्रतिनिधित्व : सीएम

रायपुर 27 नवंबर.मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में व्यापक जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदम देश के लिए लाभकारी होंगे। उन्होंने कहा कि यदि संसद में परिसीमन विधेयक लाया जाता है, तो यह स्वागतयोग्य पहल होगी। परिसीमन से लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व का विस्तार होगा तथा अधिक लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र, परिसीमन, महिला आरक्षण, कांग्रेस नेताओं के आरोपों से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसीमन से विभिन्न क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनकी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं में प्रभावी ढंग से सामने रखने का अवसर बढ़ेगा। इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण होगा। महिला आरक्षण लागू होने से देश की माताओं-बहनों को संसद और विधानसभाओं में अधिक प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। इससे नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति समाज के सभी वर्गों की सहभागिता में निहित है और प्रतिनिधित्व का विस्तार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री श्री साय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुकी है। लगातार चुनाव हारने से कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं। देश की जनता का विश्वास खोने के बाद अब उनके पास अनर्गल आरोप लगाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है।

परिसीमन को लेकर मांगों पर मैं अडिग:स्टालिन

नई दिल्ली,27 नवंबर। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें परिसीमन बिल को पास कराने की तैयारी की जा रही है। इस संविधान संसोधन के लिए संसद को दोनों ही सदनों में दो तिहाई बहुमत की आवश्यक्ता है। सरकार को एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके से समर्थन की उम्मीद है। इस बीच स्टालिन ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। उनका कहना है कि वह आज भी परिसीमन को लेकर जो उनकी मांगें हैं वह उसपर अडिग हैं। उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, डीएमके सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे इस बात की चिंता है कि क्या उसकी मांगों को इस कानून में शामिल किया जाएगा या नहीं। डीएमके का कहना है कि जब तक वह इसके प्रावधानों की जांच नहीं कर लेती तब तक वह इसके समर्थन का कोई वादा नहीं करेगी।

डीएमके ने सरकार के सामने शर्त रखी है कि परिसीमन पर 25 साल की रोक बनी रहे और सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की



संख्या में एक समान 50% की बढ़ोतरी की जाए ताकि राज्यों के प्रतिनिधित्व का आपसी अनुपात न बदले। डीएमके को डर है कि अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ती है तो उन राज्यों को नुकसान होगा, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अच्छे काम किए हैं। केंद्र सरकार ने अगर महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा का रास्ता पार कर लिया जो राज्यसभा में भी दिक्कत नहीं आएगी। वहां उसे नौ और सांसदों के जरूरत होगी, जो दल लोकसभा में साथ आएंगे उनको साथ लेकर वह राज्यसभा का आंकड़ा भी पार लेगी। लेकिन सरकार को विधेयक पास कराने के लिए लोकसभा में 36 और सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। सरकार के जो दावे हैं उनमें उसे वाायएसआरसीपी और राकांपा (एसपी) के 12 सांसदों का समर्थन मिल सकता है। 24 अन्य सांसदों के लिए उसे डीएमके के 22 का समर्थन जरूरी होगा।

लोकसभा में फिलहाल सांसदों की संख्या 540 है। दो तिहाई के लिए जरूरी 358 सांसदों के समर्थन का दावा सरकार कर रही है।

स्काईवॉक के विरोध में कांग्रेस का धरना

रायपुर, 27 नवंबर ।राजधानी का निर्माणाधीन स्काईवॉक शहर की आवश्यकता और जनहित के बजाय भाजपा नेताओं की जिद तथा सरकार की अदूरदर्शिता का प्रतीक बनता जा रहा है। लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रही इस परियोजना की उपयोगिता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शहर कांग्रेस का कहना है कि यह स्काईवॉक रायपुर के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है, जिस पर जनता की गाढ़ी कमाई खर्च की जा रही है, जबकि शहर की बुनियादी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है।स्काईवॉक निर्माण के नाम पर पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं, निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा से काफी पीछे चल रहा है। इसके अतिरिक्त, तेलघानी नाका ओवरब्रिज एवं खमतराई रेलवे अंडरब्रिज के आसपास मरम्मत कार्य के चलते स्ट्रीट लाइट और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने से आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अनेक ओवरब्रिज अंधेरे में डूबे हुए हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। जनसमस्याओं को लेकर आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर द्वारा काली मंदिर के निकट



स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में ब्रिज कॉरपोरेशन कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसजनों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के समक्ष शहर की प्रमुख समस्याओं को उठाते हुए उनके शीघ्र निराकरण की मांग की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को 7 दिन का स्पष्ट अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस अवधि में सभी समस्याओं का संतोषजनक समाधान किया जाए तथा की गई कार्रवाई की जानकारी दी जाए। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से उपस्थित रहेः शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन, पूर्व विधायक श्री कुलदीप जुनेजा, श्री विकास उपाध्याय, श्री आकाश शर्मा, श्री सुशांत डे, हीरेंद्र देवांगन श्री संदीप शर्मा, श्री दीपक चौबे, संजय अवस्थी श्री सत्तु सिंह, श्री राजेश पाल, श्री अनिल बरगे, श्री मिलिंद गौतम, श्री देव कुमार साहू, श्री विजय टंडन, सागर टांडी सुरेश धीवर, श्री सुरेश जैन, श्री सौमित्र शुक्ला, श्री आकाश दीवान, श्री अमित भारद्वाज, श्री भारत यादव, श्री फिरोज चिश्ती, श्री प्रवीण चंद्राकर, श्री वेंकट कुमार भारत यादव प्यारेलाल गायकवाड़ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

बैंक में जमा कराने पहुंची महिला के पास मिले 50 रुपये के 25 जाली नोट

रायपुर,27 नवंबर। राजधानी के दलदल सिवनी स्थित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा में शुक्रवार को पैसे जमा कराने पहुंची महिला के पास से 50-50 रुपये के नकली नोट पकड़े गए. आरोपी महिला जानकी वराठे 12,350 रुपये जमा कराने पहुंची थी. बैंककर्मियों ने उपलब्ध एडवांस मशीन से नोटों की जांच की. इस दौरान सुरक्षा संबंधी जरूरू



फीचर नहीं पाए गए. इसके बाद नकली नोट के रूप में चिन्हित कर पुलिस को सूचना दी गई. जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की दलदल सिवनी शाखा के मैनेजर संजय मिश्रा ने पंडरी थाना में शिकायत दर्ज कराई है. इसमें बताया गया कि 12 नवंबर को खाताधारक जानकी वराठे अपने खाते में 12,350 रुपये जमा कराने पहुंचा थी. कैश काउंटर पर उसने 50-100 के नोट दिए. नोटों की जांच में UV लैंप में जांच करने पर 50 रुपये के 25 जाली नोट पाए गए. बैंक मैनेजर मैनेजर संजय मिश्रा ने आरबीआई के निर्देशों का उल्लेख करते हुए बताया कि एक ट्राजेक्शन में 4 से ज्यादा जाली नोट मिलते हैं, तो एफआईआर करना अनिवार्य है. इसके तहत बैंक की तरफ से पंडरी थाने में आवेदन दिया गया है. पुलिस ने आरोपी महिला जानकी वराठे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 179 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह जाली नोट महिला के पास कैसे पहुंचे.



रायपुर। करियर में रुकावट और प्रमोशन में देरी के खिलाफ ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सुपरिटेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल टैक्स का राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. इस कड़ी में देशभर के सेंट्रल जीएसटी सुपरिटेंडेंट्स 23 से 27 नवंबर तक काला बैज पहनकर काम करेंगे. 30 साल की सेवा में सिर्फ एक प्रमोशन मिलने से सेंट्रल जीएसटी सुपरिटेंडेंट्स में भारी रोष है. अधिकारी 2014 से लंबित सीनियरिटी लिस्ट और कैडर रीस्ट्रक्चरिंग की मांग कर रहे हैं. सेंट्रल जीएसटी सुपरिटेंडेंट्स की मांगों पर सहमति जताते हुए सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन और सीआईआरएसए ने भी अपना समर्थन दिया है.

बादशाहों वाले ठाठ-बाट से रहते थे खुद को आम आदमी कहने वाले

केजरीवाल के शीश महल को सशुल्क आम लोगों को दिखाने की योजना

नईदिल्ली,27 नवंबर। राजनीति का नारा देकर सत्ता के शिखर तक पहुंचे अरविंद केजरीवाल की शाही जीवनशैली का प्रतीक बन चुका उनका चर्चित 'शीशमहल' अब आम जनता के लिए खुल रहा है। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास को मीडिया के सामने खोलने के बाद अब आम लोगों को भी इसका दीदार कराने की योजना बनाई है। इसके लिए महज 20 रुपये का प्रवेश शुल्क प्रस्तावित है। यानी अब दिल्ली का आम आदमी भी देख सकेगा कि आम आदमी की राजनीति करने वाले नेता के सरकारी आवास में बादशाहों जैसी जिंदगी के क्या-क्या इंतजाम थे।देखा जाये तो कभी आम आदमी पार्टी की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे केजरीवाल ने अपनी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनाई थी, जो न महंगी गाड़ियों का शौकीन है, न बड़े बंगले का और न ही सत्ता के पारंपरिक ठाठ-बाट का। लेकिन मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर खर्च की सामने आई रकम और वहां मौजूद महंगी सुविधाओं ने इसी सादगी की छवि पर राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी लगातार इसे 'शीशमहल' बताकर केजरीवाल को घेरती रही है। बंगले के नवीनीकरण और साज-सज्जा पर 58.83 करोड़ रुपये खर्च होने का आंकड़ा सामने आया है। आवास में 11.56 लाख रुपये का झूमर, 5.47 लाख रुपये का सोफा, 5.58 लाख रुपये की कुर्सियां, 6.79 लाख रुपये की सेंटर टेबल और 5.69 लाख रुपये के पर्दे जैसी महंगी वस्तुएं हैं। आठ बेडरूम, 12 टॉयलेट, जैकूजी बाथ, स्पा और पांच OLED टीवी जैसी सुविधाएं भी इस आवास का हिस्सा हैं।देखा जाये तो जरा इस राजनीतिक विरोधाभास पर गौर कीजिए। जिस नेता ने आम आदमी की तरह रहने और वीआईपी संस्कृति खत्म करने का दावा किया, उसके सरकारी आवास की सजावट में लाखों रुपये की चीजों की चर्चा हो रही है।



साव ने कोटा और तखतपुर को दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात

बिलासपुर,27 नवंबर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अपने जन्मदिवस के विशेष अवसर पर तखतपुर और कोटा नगर पालिका को 6.63 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने नगर पालिका कोटा में 1.98 करोड़ रुपए और तखतपुर में 4.65 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इन कार्यों से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और विकास को गति मिलेगी। तखतपुर के राम सदन में आयोजित समारोह में श्री साव ने शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय भवन निर्माण तथा तखतपुर-बरेला के मध्य मनियारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। कन्या महाविद्यालय भवन बनने से क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं मनियारी नदी पर पुल निर्माण से आवागमन सुगम होगा और आसपास के गांवों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।



कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साव ने कहा कि जन्मदिवस के अवसर पर तखतपुर क्षेत्र एवं कोटा नगर के सर्व समाज, जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजनों ने नागरिक अभिनंदन कर जो स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया है, वह उनके लिए बेहद भावुक और अविस्मरणीय है। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। श्री साव ने नगर पालिका कोटा में 1.98 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भी भूमिपूजन किया। इस राशि से नगर में नाली एवं सीसी रोड निर्माण के साथ कन्या शाला में मंच एवं शेड तथा डीकेपी शाला में शेड का निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों से नगरवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को भी सुविधाजनक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा।

श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास और जनकल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल में कोई भी गांव और शहर विकास से अछूता नहीं रहा है। तखतपुर क्षेत्र और कोटा नगर के विकास के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि तखतपुर में बीते तीन वर्षों के दौरान 60 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य की स्वीकृत हुई हैं। आने वाले समय में इन कार्यों से शहर की सुंदर तस्वीर देखने को मिलेगी।

निविदा मंजूरी के बाद 15 दिनों में कार्यादेश जारी करने के निर्देश

रायपुर. 27 नवम्बर. लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज पांचों परिक्षेत्रों, सेतु बंध, विद्युत एवं यांत्रिकी, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख अभियंता कार्यालय के सभी मुख्य अभियंताओं की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में निर्माणाधीन भवनों, सड़कों एवं पुलों के साथ ही नए कार्यों की निविदा प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ऐसे कार्यों जिनकी निविदा स्वीकृत हो गई हैं, उनके कार्यादेश चयनित ठेकेदारों एवं एजेंसियों को 15 दिनों के भीतर जारी करने के निर्देश दिए, जिससे कि वर्किंग सीजन का पूरा उपयोग करते हुए कार्यों में अच्छी प्रगति लाई जा सके। उन्होंने सभी मुख्य अभियंताओं को हर सप्ताह कम से कम दो दिन फील्ड में जाकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और गति पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की कड़ाई से मॉनिटरिंग कर उन्हें नियमित भुगतान करने को कहा। उन्होंने मुख्य अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता से लेकर उप अभियंता तक की बैठक लेकर कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री साय ने 81 विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



भिलाई, 27 नवंबर । भिलाई-चरोदा के विकास को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा प्रवास के दौरान 106.31 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 65.16 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुए 11 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 41.14 करोड़ रुपये की लागत के 70 नए कार्यों का भूमिपूजन किया। इन विकास कार्यों से भिलाई-चरोदा में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में सबसे बड़ी सौगात ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में मिली। मुख्यमंत्री ने फेज-1 में 28 करोड़ रुपये तथा फेज-2 में 29.10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कुल 57.11 करोड़ रुपये के ट्रांसपोर्ट नगर को जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा एवं खेल अधोसंरचना से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का भी लोकार्पण किया। इनमें वार्ड क्रमांक 22 चरोदा भाठापारा खेल मैदान का 1.49 करोड़ रुपये की लागत से विकास, वार्ड क्रमांक 14 नेहरू नगर में स्वामी आत्मानंद स्कूल ऑडिटोरियम का 1.49 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण तथा विद्यालय में 1.18 करोड़ रुपये के अन्य विकास कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने नगर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों की नई शुरुआत करते हुए 70 कार्यों का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भिलाई-चरोदा का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का लक्ष्य क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि भिलाई-चरोदा विकास की नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। सरकार का प्रयास है कि हर वार्ड, हर मोहल्ला और हर परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े। आने वाले समय में भी क्षेत्र को अधिक सुविधासंपन्न, सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चन्द्राकर, संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर, आईजी अभिषेक शांडिल्य, कलेक्टर अभिजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं नगरवासी उपस्थित रहे।

एक नजर

ट्रांसपोर्टर से 8 लाख की ठगी

भिलाई, 27 नवंबर । भिलाई ट्रांसपोर्टर के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। घटना की शिकायत पर पुलिस ने सेक्टर 07 भिलाई नगर निवासी राम कुमार राय ट्रांसपोर्टर हैजामुल पुलिस ने बताया कि मकान नं 2 एच, शास्त्री नगर केम्प 1 भिलाई निवासी विनोद कुमार यादव 8 लाख रुपए का ठगी किया है पीड़ित ने मकान शबाहत अमरीन के कब्जे स्वामित्व का मकान खसरा 120/4 नगर पालिका जामुल में स्थित है। मकान का विक्रिय करने का अनुबंध 75 लाख रुपए में सौदा तय किया गया शबाहत अमरीन विक्रेता को तुरंत में 8 लाख रुपए विनोद यादव के खाते से शबाहत अमरीन के खाते मे आरटीजीएस के माध्यम से 21 दिसंबर को 3 लाख, फिर 5 लाख रूपये दिया गया। उक्त ली गई रकम विनोद यादव को आरटीजीएस के माध्यम से दिया गया। फिर विनोद यादव द्वारा शबाहत अमरीन को अधिवक्ता नोटिस भेजकर अपना 8 लाख रुपए की मांग की। परेशान होकर विक्रेता शबाहत अमरी ने उक्त रकम को उसके खाते में ट्रांसफर किया विनोद ने राम कुमार राय, शबाहत अमरीन दोनो से 8 लाख -8 लाख अपने खाते में वापस ले लिया। रकम को जब पीड़ित ने रकम का डिमांड किया तो उन लोगों को घुमाते रहा। रकम नहीं देने पर परेशान होकर ट्रांसपोर्टर ने शिकायत पुलिस थाने में किया ।

आत्महत्या के कारण का पता नहीं चला

भिलाई, 26 नवंबर । भिलाई आकाशगंगा स्थित हिमालय कॉम्प्लेक्स परिसर में 15 दिन पूर्व आईफोन खरीदने पहुंचे निहाल सिंह की कॉम्प्लेक्स के टॉयलेट में फांसी लगाकर आत्महत्या मामले में सुपेला पुलिस कारण का पता नहीं लगा सकी है पुलिस मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) सहित अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की जांच की बात कह रही है। सुपेला पुलिस ने बताया कि 14 नवंबर शाम करीब 4.30 बजे निहाल सिंह पिता अरुण सिंह (28 साल) निवासी रामनगर हिमालय कॉम्प्लेक्स स्थित एक मोबाइल दुकान में आईफोन खरीदने पहुंचा था और उसने आईफोन पसंद किया और फाइनेंस की पूरी प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी।

शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को स्थानांतरण प्रमाणपत्र सेवा का प्रशिक्षण दिया गया

दुर्ग, 27 नवंबर । कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशनुसार सेवा सेतु के माध्यम से शासकीय विद्यालयों में स्थानांतरण प्रमाण पत्र सेवा को ऑनलाइन एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से 26 नवंबर को रूंगटा डेंटल कॉलेज में जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में जिले के लगभग 150 शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण के दौरान स्थानांतरण प्रमाण पत्र सेवा के ऑनलाइन आवेदन, पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निराकरण एवं संबंधित कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ही उपस्थित समस्त प्राचार्यों का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन तथा फिजिकल सिग्नेचर अपलोड करने का कार्य भी संपन्न कराया गया, जिससे आगामी समय में विद्यालय स्तर पर प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन माध्यम से समयबद्ध एवं सुचारू रूप से निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा शासकीय विद्यालयों में सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल एवं डिजिटल होगी। जिला प्रशासन द्वारा शासकीय सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आम नागरिकों तक सरलता एवं सुगमता से उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

संरक्षित नमी का लाभ लेने किसान जीरो टिलेज तकनीक से करें बुवाई

दुर्ग, 27 नवंबर । जिले में गेहूं एवं चना की बुवाई शुरू हो चुकी है। इस वर्ष खेतों में पर्याप्त नमी संरक्षित होने के कारण किसानों को इसका लाभ लेने के लिए जीरो टिलेज (शून्य जुताई) तकनीक से बुवाई करने की सलाह दी जा रही है। इस तकनीक से धान की कटाई के बाद बिना पारंपरिक जुताई किए सीधे खेत में रबी फसलों की बुवाई की जा सकती है।

जीरो टिलेज तकनीक से खेती करने पर खेत की बार-बार जुताई की आवश्यकता नहीं होती, जिससे ट्रैक्टर एवं डीजल पर होने वाला खर्च कम होता है। साथ ही खेत की तैयारी में लगने वाला समय बचता है और फसलों की समय पर बुवाई संभव हो पाती है। इस तकनीक के लिए विशेष जीरो टिलेज सीड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। गेहूं, चना, मसूर एवं अन्य रबी फसलों की खेती में यह तकनीक उपयोगी है।जीरो टिलेज तकनीक के प्रमुख लाभशून्य जुताई से मिट्टी में उपलब्ध नमी सुरक्षित रहती है, जिससे फसल की शुरुआती अवस्था में लाभ मिलता है। इसके अलावा मिट्टी की संरचना एवं जैविक गतिविधियों को बनाए रखने, मिट्टी के कटाव को कम करने तथा फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन में भी मदद मिलती है। नमी के बेहतर संरक्षण से सिंचाई की आवश्यकता कम हो सकती है और डीजल की खपत घटने से पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलता है।

भूमिपूजन



53.57 लाख की लागत से महामाया मंदिर रोड पर होगा विकास कार्य

भिलाई, 27 नवंबर । नगर के वार्ड क्रमांक 10 में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जी रोड से शीतला मंदिर तक महामाया मंदिर रोड पर 53 लाख 57 हजार रुपये की लागत से कवर्ड आरसीसी नाली निर्माण, सीसी रोड निर्माण एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य का भूमिपूजन विधिवत पूजा-अर्चना के साथ संपन्न हुआ। पंडित एन.के. त्रिपाठी ने पूजा-अर्चना कर भूमिपूजन की धार्मिक विधि संपन्न कराई। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल उपस्थित रहे, जबकि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मीना वर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस विकास कार्य के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलने के साथ जल निकासी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

संविधान दिवस एवं ज्योतिबा फुले स्मृति दिवस समारोह बटरेल में 28 को

पाटन, 27 नवंबर (तछसं.)। आसरा पाटन ग्रुप के तत्वावधान में शनिवार, 28 नवंबर को दक्षिण पाटन के शासकीय पूर्व माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बटरेल में संविधान दिवस एवं शिक्षा क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले के स्मृति दिवस पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक राजेन्द्र मारकंडे ने बताया कि समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों में संविधान के प्रति जागरूकता, शिक्षा के महत्व तथा कैरियर निर्माण के प्रति मार्गदर्शन प्रदान करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन के साथ होगा। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत एवं उद्बोधन होगा। समारोह में संविधान विशेषज्ञ विनोद कोसले द्वारा संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों एवं नागरिक जागरूकता पर जानकारी दी जाएगी। वहीं फिल्म निर्माता-निर्देशक हेमलाल चतुर्वेदी लोकगीतों की प्रस्तुति देंगे। विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारी विद्यार्थियों को संविधान एवं शिक्षा के माध्यम से कैरियर निर्माण के संबंध में मार्गदर्शन देंगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।



कृषि स्थायी समिति की बैठक में गन्ना बोनस,धान खरीदी एवं कृषि विभागीय योजनाओं की समीक्षा

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

कवर्धा,27 नवंबर। जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति की बैठक आज सभापति कृषि स्थायी समिति श्रीराम कुमार भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्य श्री डॉ. बीरेंद्र कुमार साहू एवं श्री राजकुमार मेरावी सहित कृषि एवं समवर्गीय विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में निर्धारित एजेंडे के अनुसार गन्ना बोनस एवं धान खरीदी के संबंध में चर्चा की गई। इसके साथ ही कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभागों के कार्यों तथा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की योजनाओं, गतिविधियों एवं कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी समिति के सभापति एवं सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की। सदस्यों द्वारा विभिन्न विभागीय विषयों पर चर्चा कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई।गन्ना कटाई के संबंध में चर्चा के दौरान शक्कर कारखाना के अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि जिले में गन्ना फसल के रकबे एवं उत्पादन को ध्यान में रखते हुए गन्ना कटाई कार्य को सुगम बनाने के लिए कम से कम 04 गन्ना कटाई हार्वेस्टर की अत्यंत आवश्यकता है। हार्वेस्टर की उपलब्धता से किसानों को गन्ना कटाई के समय मजदूरों की कमी एवं उनकी उपलब्धता संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। इससे गन्ना कटाई का कार्य समय पर एवं सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सकेगा। बैठक में प्रस्ताव क्रमांक-01 के अंतर्गत पशुपालन विभाग की व्यक्तिमूलक योजनाओं के प्रकरणों की सूची अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत सूची पर विस्तृत चर्चा के उपरांत कृषि स्थायी समिति द्वारा सूची का अनुमोदन किया गया। बैठक के अंत में सभापति श्री राम कुमार भट्ट एवं समिति के सदस्यों की अनुमति से सचिव, कृषि स्थायी समिति एवं उप संचालक कृषि द्वारा सभा की समाप्ति की घोषणा की गई।

शशि सिन्हा,योगिता चंद्राकर को महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने पर ताम्रध्वज ने दी बधाई



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

उतई, 27 नवंबर। प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने अपने निज निवास में महापौर, नगर निगम रिसाली श्रीमती शशि सिन्हा जी एवं श्रीमती योगिता चंद्राकर जी को महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी मिलने पर गुलदस्ता भेंटकर एवं मुँह मीठा कर हार्दिक बधाई दी।

इस अवसर पर पूर्व गृहमंत्री ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों अपने अनुभव, समर्पण और संगठनात्मक क्षमता से महिला कांग्रेस को और अधिक सशक्त बनाएंगी तथा महिलाओं के हक और आवाज को मजबूती से बुलंद करेंगी।

उन्होंने दोनों के उज्ज्वल कार्यकाल के लिए ढेरों शुभकामनाएं दीं। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बौनेपन से जूझते पीयूष का मासूम जवाब सुनकर भर आती हैं आंखें, कहता है-सोचने वाला काम पूरा नहीं होता

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



भिलाई, 26 नवंबर । आमतौर पर किशोर उम्र के बच्चों से उनके भविष्य के सपनों के बारे में पूछा जाए तो वे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या अधिकारी बनने की इच्छा जताते हैं, लेकिन किशन चौक शारदापारा निवासी पीयूष का जवाब कुछ अलग है। बौनेपन के कारण शारीरिक रूप से अलग पहचान रखने वाले पीयूष से जब पूछा गया कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो उसने भावुक होकर कहा, कुछ सोचा नहीं हूं, क्योंकि सोचने वाला काम पूरा नहीं होता है। उसका यह जवाब मन को भीतर तक छू जाता है। पीयूष किशन चौक, शारदापारा में अपने परिवार के साथ रहता है। उसके पिता रूप सिंह पेंटिंग का काम करते हैं, जबकि मां सत्यभामा भी कामकाजी हैं। परिवार में पीयूष के अलावा उसका छोटा भाई निहाल और बहन निहारिका हैं, जो कक्षा दूसरी में पढ़ते हैं। पीयूष स्वामी आत्मानंद विद्यालय, जेपी नगर में कक्षा नौवीं का विद्यार्थी है। उसे शासन की ओर से पेंशन भी मिलती है। परिवार के अनुसार उसे किसी तरह की विशेष परेशानी नहीं है और वह अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है। तरुण छत्तीसगढ़ ने एक कार्यक्रम के दौरान जब पीयूष से पूछा कि बड़ा होकर वह क्या बनना चाहता है, तो उसका जवाब सुनकर मन भावुक हो जाता है। उसने बड़ी सहजता और उदासी के साथ कहा, अभी कुछ सोचा नहीं हूं, क्योंकि सोचने वाला काम पूरा नहीं होता है। एक बच्चे के मुंह से निकले ये शब्द कई सवाल खड़े करते हैं। जिस उम्र में बच्चे अपने भविष्य के सपनों को संजोते हैं, उस उम्र में पीयूष का यह जवाब उसकी सोच और परिस्थितियों के प्रति एक अलग नजरिया सामने लाता है। उसके भीतर भी दूसरे बच्चों की तरह सपने होंगे, लेकिन फिलहाल उसने अपने भविष्य को किसी एक मंजिल से नहीं जोड़ा है।

पीयूष की कहानी केवल उसके कम कद की वजह से अलग नहीं है, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए जीवन की राह पर आगे बढ़ रहा है। जरूरत है कि उसे भी दूसरे बच्चों की तरह समान अवसर, प्रोत्साहन और आगे बढ़ने का भरोसा मिले। आखिर किसी बच्चे का भविष्य उसकी शारीरिक बनावट से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा, इच्छाशक्ति और उसे मिलने वाले अवसरों से तय होना चाहिए। एक समय था जब सर्कस में बौनेपन वाले कई कलाकार हास्य प्रस्तुतियों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करते थे। वे अपनी कला से लोगों को हंसाते और तालियां बटोरते थे। लेकिन बदलते दौर में सर्कस की दुनिया भी सिमटती चली गई और ऐसे मंचों पर मिलने वाले रोजगार के अवसर भी कम हो गए। आज जरूरत इस बात की है कि बौनेपन वाले लोगों को उनकी शारीरिक बनावट के बजाय उनकी योग्यता, हुनर और प्रतिभा के आधार पर रोजगार के अवसर मिलें। पीयूष जैसे बच्चों के सामने भी भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बजाय संभावनाओं के दरवाजे खुलने चाहिए। पीयूष की मासूम बात भले ही कुछ पल के लिए भावुक कर दे, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि उसके सपनों को उड़ान देने में परिवार, समाज और व्यवस्था सभी अपनी भूमिका निभाएं।

भिलाई विद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा दिवस मनाया गया



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 27 नवंबर । भिलाई विद्यालय सेक्टर-2 में वार्षिक क्रीड़ा दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। मुख्य अतिथि बीएसपी के मुख्य महाप्रबंधक प्रशांत ओझा एवं विशिष्ट अतिथि शिखा दुबे ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पांच स्वर्ण, चार रजत एवं दो कांस्य पदक हासिल किए। राज्य स्तरीय अंडर-19 बालक वर्ग में आलोक कुमार सागर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। हाउसवार प्रतियोगिताओं में पीस हाउस सर्वश्रेष्ठ रहा, जबकि होप हाउस उपविजेता बना। प्राचार्य विजय सिंह पवार सहित शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित रहे।

सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में मनाया गया संविधान दिवस ; विद्यार्थियों ने ली संविधान रक्षा की शपथ

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



छुरा, 27 नवंबर। नगर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में भारतीय संविधान दिवस का आयोजन अत्यंत गरिमामय, अनुशासित एवं उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। इस विशेष अवसर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को देश के सर्वोच्च विधान की महत्ता, लोकतांत्रिक मूल्यों और एक जागरूक नागरिक के रूप में उनके दायित्वों से अवगत कराना था। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय परिसर में भाषण, निबंध, प्रश्नोत्तरी एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों सहित विभिन्न ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

इस गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि एवं मार्गदर्शक के रूप में संस्था के निदेशक जॉर्ज जैकब, प्राचार्य बिंदु जॉर्ज जैकब तथा प्रबंधक आशीष जैकब विशेष रूप से मंचासीन रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य बिंदु जॉर्ज जैकब ने अत्यंत सारगर्भित एवं प्रेरक उद्बोधन दिया। उन्होंने भारतीय संविधान के गौरवशाली इतिहास, इसके निर्माण की प्रक्रिया और डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित संविधान निर्माताओं के अमूल्य योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि संविधान हमें न केवल मौलिक अधिकार प्रदान करता है, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्यों का भी बोध कराता है। उद्बोधन के पश्चात प्राचार्य बिंदु जॉर्ज जैकब ने उपस्थित सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया। इस दौरान सभी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता और लोकतांत्रिक आदर्शों को अक्षुण्ण बनाए रखने की निष्ठापूर्वक शपथ ली।संपूर्ण कार्यक्रम का मंच संचालन शिक्षक अशोक महानंद द्वारा अत्यंत सधे हुए और प्रभावशाली अंदाज में किया गया, जिससे पूरे आयोजन में ऊर्जा और अनुशासन बना रहा। समारोह के समापन अवसर पर उप-प्राचार्य लोवित रत्नाकर ने मंच पर उपस्थित अतिथियों, कार्यक्रम को सफल बनाने वाले शिक्षकों एवं उत्साही विद्यार्थियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के औपचारिक समापन की घोषणा की।

श्रमिकों का आधार आधारित ई-केवाईसी एवं अभिलेख अद्यतन कार्य जारी, 669 शिविरों में 27,718 आवेदन प्राप्त

दुर्ग, 27 नवंबर। जिले में पंजीकृत श्रमिकों के अभिलेखों को आधार कार्ड के अनुरूप अद्यतन करने का कार्य लगातार जारी है। श्रम विभाग द्वारा ई-केवाईसी एवं आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से पात्र श्रमिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 669 शिविर आयोजित कर 27,718 पंजीकृत श्रमिकों के श्रम पंजीयन कार्ड को आधार कार्ड के अनुरूप अद्यतन करने के आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं।सहायक श्रमायुक्त से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में 1 लाख 14 हजार 36 श्रमिकों का नया पंजीयन लंबित नहीं है, बल्कि ये सभी पूर्व से पंजीकृत श्रमिक हैं, जिनके पंजीयन अभिलेखों का आधार कार्ड से मिलान एवं आवश्यक अद्यतन किया जा रहा है।

धान का उचित मूल्य मिलने से किसानों के चेहरे पर दिखी खुशी

धमतरी 27 नवंबर। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम किसानों के जीवन में दिखाई देने लगा है। इसी क्रम में धमतरी जिले के पोटियाडीह धान उपार्जन केंद्र से जुड़े दो किसान श्री चुम्मन लाल एवं श्रीमती वेदबाई मुजगन (पति-पत्नी) ने धान की बिक्री के माध्यम से बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त किया है।

दोनों किसानों ने अपनी उपज का 26.90 क्विंटल गोल्डन धान राइस मिल में विक्रय कर 3,050 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राशि राशि प्राप्त राशि एवं कृषि उन्नत योजना अंतर्गत आदान सहायता मिलने वाली 659 रुपये प्रति क्विंटल की राशि को जोड़ने पर उन्हें कुल 3,709 रुपये प्रति क्विंटल का आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। चुम्मन लाल ने 20.90 क्विंटल एवं श्रीमती वेदबाई ने 6.00 क्विंटल धान बेचा है ।मालूम हो कि छत्तीसगढ़ शासन की कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026-27 से पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में दी जा रही है। यदि किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता राशि दी जाती है ।

दोनों किसानों ने बताया कि खेती-किसानी में लागत लगातार एक महत्वपूर्ण विषय रही है। ऐसे में शासन द्वारा धान उत्पादक किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के साथ आदान सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था किसानों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है। धान विक्रय से प्राप्त नकद राशि और आदान सहायता की राशि से खेती की आगामी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे कृषि कार्यों के प्रति भरोसा और उत्साह भी बढ़ा है। किसान श्री चुम्मन लाल एवं श्रीमती वेदबाई मुजगन ने इस व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की किसान हितैषी नीतियों से किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। आदान सहायता योजना के माध्यम से मिलने वाली अतिरिक्त राशि खेती की लागत की भरपाई करने और आगामी कृषि कार्यों की तैयारी में उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार की यह पहल सराहनीय है।दोनों किसानों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान हितों को प्राथमिकता देते हुए शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं राज्य शासन को धन्यवाद देते हुए धान खरीदी व्यवस्था से जुड़े समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। किसानों का कहना है कि शासन की योजनाओं का लाभ मिलने से न केवल आर्थिक राहत मिलती है, बल्कि खेती को लेकर सकारात्मक सोच और भविष्य के प्रति विश्वास भी मजबूत होता है। किसानों ने उम्मीद जताई कि इसी तरह किसान हितैषी योजनाओं और सहयोगात्मक व्यवस्था से कृषि क्षेत्र निरंतर समृद्ध होगा तथा किसानों की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ बनेगी।

संविधान दिवस पर अधिकारियों-कर्मचारियों ने किया संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन

दुर्ग, 27 नवंबर । संविधान दिवस के अवसर पर आज कलेक्टोरेट, तहसील एवं ग्राम स्तर सहित शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, नगरीय निकायों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों एवं संगठनों में भारतीय संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया गया। इस दौरान अधिकारी-कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर संविधान के मूल आदर्शों एवं सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखने की शपथ ली।

पारदर्शी उर्वरक वितरण के लिए एफएफएस मोबाइल एप एवं टोकन प्रणाली का दिया प्रशिक्षण

दुर्ग, 27 नवंबर। रबी सीजन 2026-27 में किसानों को समय पर, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने तथा कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से जिले में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल मोबाइल एप आधारित टोकन व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत किसानों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ना और उर्वरक प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाना है। जिले में एफएफएस (फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल) टोकन वितरण की कार्यप्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा किसानों को इसके माध्यम से खाद क्रय करने की प्रक्रिया समझाने के लिए अब तक 362 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

निधन

सोनमती राजभर

भिलाई, 27 नवंबर । छत्तीसगढ़ राजभर महासभा के अध्यक्ष नरसिंह राजभर एवं भाजपा नेता भानुप्रताप राय की माता श्रीमती सोनमती राजभर, पत्नी स्वर्गीय स्वामीनाथ राजभर का बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन से परिवार एवं राजभर समाज में शोक व्याप्त है।दिवंगत सोनमती राजभर की अंत्येष्टि बुधवार को रामनगर मुक्तिधाम में संपन्न हुई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की तथा शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान किया।



एक नजर

बाल विवाहमुक्त जिला बनाने के लिए कलेक्टर ने की अपील

बलौदाबाजार, 27 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने में



सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की है। उन्होंने 27 नवंबर को बाल विवाह उन्मूलन दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभाओं सहित स्कूलों, महाविद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करने तथा बाल विवाह नहीं करने, नहीं होने देने और इसका विरोध करने की शपथ लेने का आह्वान किया है। कलेक्टर ने अपने संदेश में कहा है कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति एवं दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के शारीरिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बाधित करता है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जनजागरूकता और सामूहिक प्रयास आवश्यक है। उन्होंने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, अधिकारी-कर्मचारियों एवं आम नागरिकों से बाल विवाह उन्मूलन अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने तथा बच्चों के सुरक्षित एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए बाल विवाह मुक्त जिला बनाने का संकल्प लेने की अपील की है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायलय में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 29 को

बलौदाबाजार,27 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में सीधी भर्ती हेतु स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 हिन्दी, स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 अंग्रेजी एवं सहायक ग्रेड-3 पद के लिए लिखित परीक्षा 29 नवम्बर 2026 दिन रविवार को नियत की गई है। परीक्षा के संबंध में प्रवेश पत्र एवं अन्य जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार के शासकीय वेबसाइट baloda-bazar.dcourts.gov.in पर जारी किया गया है। जिसे अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है।

अतिथि क्रीड़ाधिकारी भर्ती निरस्त

बलौदाबाजार, 27 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय सिमगा मे अतिथि क्रीड़ाधिकारी के 1 पद पर भर्ती प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया हैं। प्राचार्य ने बताया है कि उक्त पद पर भर्ती हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में वृध्दि कर 28 नवम्बर 2026 तक की गई थी। अब पूर्व भर्ती प्रकिया मे प्राप्त हुए आवेदनों का ही नियमानुसार परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

लोकभवन में मनाया गया संविधान दिवस

रायपुर, 27 नवंबर। लोकभवन रायपुर में आज संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस के अवसर पर लोकभवन सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। राज्यपाल की उप सचिव सुश्री निधि साहू सहित सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। यह संविधान के मूल सिद्धांतों, शासन की प्रकृति और मुख्य उद्देश्यों का संक्षिप्त परिचय देती है, जिसकी शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। संविधान की उद्दिशका इस प्रकार से है- हम, भारत के लोग, भारत को एक 1(संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य , बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और 2 (राष्ट्र की एकता और अखंडता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

अपर कलेक्टर ने धान उपार्जन केन्द्र कोलिहापुरी एवं तहसील कार्यालय लाल बहादुर नगर का किया निरीक्षण

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



राजनांदगांव 27 नवंबर। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय ने डोंगरगढ़ विकासखंड के धान उपार्जन केन्द्र कोलिहापुरी एवं तहसील कार्यालय लाल बहादुर नगर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने धान उपार्जन केन्द्र कोलिहापुरी में किसानों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने किसानों के खसरों में शून्य रकबा, अन्य फसल एवं पड़ती दर्ज होने से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि धान उपार्जन केन्द्र कोलिहापुरी अंतर्गत आने वाले 6 ग्रामों के लगभग 300 खसरों में शून्य रकबा प्रदर्शित हो रहा था। इनमें से 270 खसरों का सत्यापन कर सही प्रविष्टि दर्ज कर ली गई है। शेष खसरों का मौके पर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसी तरह डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) में 314 खसरों में अन्य फसल एवं पड़ती दर्ज हो गई थी। इन खसरों का भौतिक सत्यापन कर धान की सही प्रविष्टि दर्ज करते हुए से 865 खसरों का भौतिक सत्यापन कर सही फसल की प्रविष्टि दर्ज करते हुए प्रकरण जिला कार्यालय भेजे जा रहे हैं।

अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय ने तहसील कार्यालय लाल बहादुर नगर का औचक निरीक्षण कर किसानों से प्राप्त दावा-आपत्तियों एवं उनके निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि अन्य फसल एवं पड़ती दर्ज होने के संबंध में अब तक 1740 खसरों पर दावा-आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें प्रकरण जिला कार्यालय भेजे जा रहे हैं। शेष खसरों से संबंधित दावा-आपत्तियों का निराकरण पटवारियों द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन कर कराया जाएगा। अपर कलेक्टर ने किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाते हुए निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय ने निर्माणाधीन तहसील कार्यालय लाल बहादुर नगर के भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार श्री नीलकंठ जनबंधु, नायब तहसीलदार श्री राजेश नेताम, सहकारिता निरीक्षक श्री महेश्वरी, समिति प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी एवं किसान उपस्थित थे।

जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारु रूप से जारी

- अब तक 11 हजार 3 किसानों ने बेचा धान
- आज 1 हजार 583 किसानों से 6 हजार 519.48 मीट्रिक टन धान की खरीदी
- जिले में अब तक 42 हजार 535.24 मीट्रिक टन धान की खरीदी
- अवैध धान के भंडारण एवं परिवहन पर जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई
- अवैध धान के 36 प्रकरणों में 3 हजार 170.30 क्विंटल धान जब्त



राजनांदगांव 27 नवंबर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से जारी है। जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में किसान अपनी उपज का विक्रय कर रहे हैं। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार आज जिले के 122 धान उपार्जन केन्द्रों के लिए कुल 1 हजार 710 टोकन जारी किए गए थे, जिसमें 7 हजार 647.38 मीट्रिक टन धान विक्रय के लिए पंजीकृत था। जारी टोकन के विरूद्ध आज 1 हजार 583 किसानों से 6 हजार 519.48 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। टोकन प्राप्त करने वाले 92.57 प्रतिशत किसानों ने आज अपनी उपज का विक्रय किया। जिले में धान खरीदी प्रारंभ होने से अब तक कुल 11 हजार 3 किसानों से 42 हजार 535.24 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। आगामी दिवस 27 नवम्बर 2026 को जिले के 122 धान उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय के लिए 1 हजार 716 टोकन जारी किए गए हैं, जिसमें 7 हजार 847.16 मीट्रिक टन धान विक्रय के लिए पंजीकृत है।

अवैध धान के भंडारण एवं परिवहन पर लगातार कार्रवाई

जिले में धान के अवैध भंडारण, परिवहन एवं उपार्जन केन्द्रों में अवैध धान खपाने के प्रयासों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारियों द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में आज तहसीलदार द्वारा अवैध धान के भंडारण के 2 प्रकरण दर्ज कर कुल 432 कट्टा (172.80 क्विंटल) धान जप्त किया गया। इसके अंतर्गत धान उपार्जन केन्द्र केसाल में 192 कट्टा (76.80 क्विंटल) तथा ग्राम उमरवाही में 240 कट्टा (96 क्विंटल) धान जप्त किया गया। स्वयं की धान की फसल की कटाई किए बिना अवैध रूप से धान का भंडारण किए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की गई। जिले में अब तक अवैध धान के 36 प्रकरण दर्ज कर 3 हजार 170.30 क्विंटल धान, 7 हजार 522 बारदाना एवं 4 वाहन जप्त किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान के भंडारण, परिवहन एवं विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जिले के किसान अपनी उपज की कुछ मात्रा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन केन्द्रों में विक्रय कर कृषक उन्नति योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं शेष उपज का कृषि उपज मंडी में विक्रय कर अतिरिक्त लाभ अर्जित कर रहे हैं। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज कृषि उपज मंडी राजनांदगांव पहुंचकर ऐसे किसानों से चर्चा की तथा उन्हें प्रोत्साहित किया।

शिवनाथ तट पर गंगा आरती की गई



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

सिमगा 27 नवंबर। कार्तिक पुर्णिमा के अवसर पर शिवनाथ नदी के तट पर भव्य गंगा आरती संपन्न हुआ। देव दिवाली पर शिवनाथ नदी के तट पर देव दिवाली एवं कार्तिक पुर्णिमा के पावन अवसर पर प्राचीन शिवनाथ मंदिर एवं शिवनाथ नदी तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया था। पूरे नदी तट को रंगोली एवं फूलों से आकर्षण ढंग से सजाया गया था । इस गंगा आरती के अवसर पर 25 सौ दीप प्रज्जवलित कर अपनी आस्था प्रकट की, दीपो की रोशनी से शिवनाथ नदी का तट जगमगा उठा।वही श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी भी की। सिमगा नगर के पंडित दउवा प्रसाद भारद्वाज ने आरती के पूर्व मंत्रोचार के साथ मां गंगा, भोलेनाथ, श्री राम एवं भारतमाता की मंगलआरती की गई साथ ही सेवा मंडली द्वारा श्रीराम जी की भजन गाकर शमा बांधा गया। इस गंगा आरती में सिमगा नगर के सौकड़ो श्रद्धालुओं ने बढ चढकर? हिस्सा लिया साथ ही वहा प्रसादी वितरण की गयी इस गंगा आरती में विशेष रूप से नगर पालिका के अधिकारी श्री शशिभूषण श्रीवास्तव, पार्षदगण, एल्डरमेन, व्यासनारायण गुप्ता, बसंती गुप्ता, शारदा भोसले, सुवर्णा ओमप्रकाश शर्मा, श्वेता गुप्ता, सुरज गुप्ता, योगराज देवांगन,अनुप तिवारी, निरज ठाकुर एवं गौ सेवा समिति सिद्धेश्वर शिवमंदिर के सदस्यगण एवं पत्रकारगण आदि उपस्थित थे।

नगर निगम में भारत के संविधान के प्रस्तावना का किया सामूहिक पाठ



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

राजनांदगांव 27 नवंबर। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी संविधान दिवस के अवसर पर आज 26 नवम्बर 2026 को नगर निगम में भारतीय संविधान के प्रस्तावना (उद्देशिका) का सामुहिक पठन किया गया।

आज नगर निगम सभागृह में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वरिष्ठ पार्षद श्री शिव वर्मा एवं राजस्व अधिकारी श्री मोबिन अली की उपस्थिति में संविधान के प्रस्तावना (उद्देशिका) का पठन किया गया कि हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिये दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते है। राजस्व अधिकारी श्री मोबिन अली ने भारत के संविधान पर प्रकाश डालते हुये प्रस्तावना को आत्मसात करने सामुहिक पठन कराया। इस अवसर पर सहायक अभियता श्रीमती ज्योति साहू, प्र.सहायक अभियंता श्रीमती गरिमा वर्मा, सहित अधिकारियो व कर्मचारियों ने भारत का संविधान के प्रस्तावना का सामुहिक पठन किया।

महापौर एवं कलेक्टर ने शहर के निर्माणाधीन स्टेशनपारा रेलवे अंडरब्रिज का किया निरीक्षण

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



राजनांदगांव 27 नवंबर। महापौर श्री मधुसूदन यादव एवं कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज राजनांदगांव शहर के निर्माणाधीन स्टेशनपारा रेलवे अंडरब्रिज का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अब तक पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों एवं शेष कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान रेलवे अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से अंडरब्रिज निर्माण की वर्तमान स्थिति तथा कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा के संबंध में विस्तृत जानकारी ली।

कलेक्टर ने निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्टेशनपारा रेलवे अंडरब्रिज शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण को प्राथमिकता देते हुए शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि नागरिकों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। उन्होंने रेलवे अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। स्टेशनपारा रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण पूर्ण होने से क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी तथा नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। इस दौरान रेलवे के अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

नगर निगम शहर के सभी सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई करवा रहा

रायपुर 27 नवंबर। नगर निगम रायपुर द्वारा शहर के सभी सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव एवं नियमित सफाई हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। रायपुर शहर के सभी सार्वजनिक शौचालयों की सफाई हेतु एजेंसी नियुक्त है एवं सफाई कार्य नियमित रूप से कराया जा रहा है। सार्वजनिक शौचालय निगरानी एपफ का शुभारंभ विगत दिनांक 19 नवम्बर 2026 को किया गया है। उक्त एप के माध्यम से दिन में 2 बार सफाई की मॉनिटरिंग की जावेगी। सभी एजेंसियों को इस एप के संचालन हेतु प्रशिक्षण दे दिया गया है एवं इसी एप के माध्यम से कार्य प्रारंभ हो गया है। सफाईकर्मी द्वारा सफाई के पूर्व एवं पश्चात् का जियो-टैग्ड फोटो एप पर अपलोड की जावेगी, जिसकी प्रतिदिन जोन स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की जावेगी। शौचालयों में पानी, बिजली एवं आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

गांजा तस्करी मामले में दूसरा आरोपी1.05 किलो गांजा और स्कूटी सहित गिरफ्तार

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



राजनांदगांव, 27 नवंबर। गांजा परिवहन और बिक्री के मामले में डोंगरगढ़ पुलिस ने एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी दिगंबर ठाकुर के कब्जे से 1.050 किलोग्राम गांजा और ज्यूपिटर स्कूटी सहित कुल 1 लाख 2 हजार रुपये का सामान जब्त किया है। मामले में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी पालेश्वर सेन को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 24 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पालेश्वर सेन निवासी रामाटोला, थाना डोंगरगढ़, स्कूटी में गांजा रखकर बिक्री और परिवहन कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने मोचीपारा में राधेलाल मालाकार के घर के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा था।

उसके कब्जे से नीले रंग की प्लास्टिक थैली में रखा 390 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत 19,500 रुपये बताई गई, तथा स्कूटी क्रमांक ष्ट्त 08ञ्ज 2189, कीमत 40 हजार रुपये, जब्त की गई थी। इस मामले में अपराध क्रमांक 693/2026, धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर पालेश्वर सेन को 25 नवंबर को जेल भेज दिया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने दिगंबर ठाकुर की पतासाजी कर उसे हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दिगंबर ने पालेश्वर सेन को गांजा बिक्री के लिए देने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की ज्यूपिटर स्कूटी क्रमांक CG 08 BJ 2938 की डिक्की से 1.050 किलोग्राम गांजा बरामद किया।जब्त गांजे की कीमत 52 हजार रुपये और स्कूटी की कीमत 50 हजार रुपये बताई गई है। दोनों की कुल कीमत 1 लाख 2 हजार रुपये है। आरोपी दिगंबर ठाकुर (26), पिता खिलावन ठाकुर, निवासी रामपुर, थाना लालबाग, राजनांदगांव के विरुद्ध धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन और एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख, प्रशिक्षु उप निरीक्षक महेश मंडावी, आरक्षक अविलेश साहू, मिथलेश पटेल, इंद्रभान और रामखिलाव सिन्हा का सराहनीय योगदान रहा।

अतिक्रमण हटाने निगम ने की कार्रवाई

- हाट बाजार में महिला सामुदायिक शौचालय के पास से 6 ठेले- खोमचे हटाये

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



राजनांदगांव 27 नवंबर। नगर निगम सीमांतर्गत अवैध निर्माण एवं शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर प्रभावी रूप से रोकथाम करने के लिये निगम आयुक्त श्री जी.आर. मरकाम द्वारा गठित अतिक्रमण दस्ता शहर में निरीक्षण कर और शिकायत के आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रही है। आज हाट बाजार में महिला सामुदायिक शौचालय के पास से 6 ठेला खोमचा हटाने की कार्यवाही की गई।

रोड एवं चैक चैराहो में अतिक्रमण कर ठेला खोमचा रखने या मटेरियल व मलमा रखने की जानकारी होने पर नगर निगम की गठित दल अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रही है। वही उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान अतिक्रमित पाये जाने पर भी कार्यवाही की जा रही है। आज आयुक्त के निर्देश पर हाट बाजार में महिला सामुदायिक शौचालय के पास ठेला खोमचा रखकर व्यवसाय किया जा रहा था। जिसे हटाने संबंधितो को समझाईस दी गयी थी, समझाईस उपरांत भी नही हटाने पर महिलाओ को शौचालय आने जाने में हो रही असुविधा को देखते हुए आज शौचालय के पास के 6 ठेला खोमचा हटाने की कार्यवाही की गयी। आयुक्त श्री मरकाम ने अतिक्रमण दस्ता से कहा कि हाट बाजार या उसके आस पास अतिक्रमण करने या अवैध रूप से रखे ठेला, खोमचा सुगम आवागमन की दृष्टिकोण से हटाया जाए। साथ ही शहर में जहॉ जहॉ पर अतिक्रमण की शिकायत या अतिक्रमण पाये जाने पर उसे तत्काल हटाया जाये और संबंधित के विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाये। उन्होंने व्यवसायियो से भी कहा है कि वे अपने दुकान के अंदर ही समान रखे, दुकान के बाहर समान रखने पर यातायात बाधित होती है, इसी प्रकार नाली के उपर ठेला खोमचा रखने से साफ सफाई बांधित होने के साथ साथ गंदगी फैलती है। उन्होंने कहा कि सडक या सार्वजनिक स्थल में निर्माण समाग्री न रखे, अन्यथा अर्थदण्ड के साथ साथ जप्ती की कार्यवाही की जावेगी।

डॉ. गीतेश अमरोहित ने रचा छत्तीसगढ़ भाषा का पहला वृहद् छत्तीसगढ़ी व्याकरण



रायपुर 27 नवंबर। मेडिकल कॉलेज रायपुर के भूतपूर्व चिकित्सक डा. गीतेश अमरोहित ने समग्र छत्तीसगढ़ी व्याकरण नाम से एक किताब लिखी है। इस तरह की किताब राज्य में पहली बार बनाई गई है। यूं तो छत्तीसगढ़ी का पहला व्याकरण अठारहवीं शताब्दी में हिन्दी व्याकरण के पहले ही हीरालाल काव्योपाध्याय ने लिख दिया था, जिसे अंग्रेजों ने अपने गजेटियर में प्रकाशित करवाया था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पीएससी, व्यापम और अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण के अलग से प्रश्न पूछे जाने लगे। लेकिन बाजार में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों का अभाव था। इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉ. गीतेश कुमार अमरोहित ने समग्र छत्तीसगढ़ी व्याकरण नामक एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक पूर्णतः सीजी पीएससी के सिलेबस पर आधारित है। चार सौ पचास से अधिक पृष्ठों वाली इस किताब की खासियत यह है कि छत्तीसगढ़ी वर्णमाला से किताब की शुरूवात होती है। पचास से अधिक अध्यायों में छत्तीसगढ़ी व्याकरण के समस्त पहलुओं को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास हेतु प्रश्न भी प्रस्तुत किए गए हैं। पुस्तक की एक खास बात यह है कि राज्य में पहली दफे छत्तीसगढ़ी भाषा में रस, छंद, अलंकार, निबंध, पत्र लेखन व अपठित गद्यांश को भी स्थान दिया गया है। समग्र छत्तीसगढ़ी व्याकरण पुस्तक में छत्तीसगढ़ी भाषा में शासकीय टिप्पणियां, प्रशासनिक शब्दावली, शासकीय पत्र लेखन का भी समावेश है। इससे शासकीय कार्य में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करने में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आसानी होगी। दूसरी ओर इसी पुस्तक के एक अलग खंड में वृहद छत्तीसगढ़ी शब्दकोश भी प्रदर्शित है। इस शब्दकोश की खासियत यह है कि छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिन्दी अर्थ के साथ अंग्रेजी अर्थ और उच्चारण भी प्रदर्शित हैं। लंबे समय तक मेकाहारा में चिकित्सक पद पर सेवा देने के पश्चात डॉ. गीतेश कुमार अमरोहित अब पूर्णरूपेण छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य लेखन कर रहे हैं।

अहंकार से नुकसान होता है कांग्रेस मानती नहीं है

अहंकार से नुकसान ही होता है क्योंकि अहंकार के कारण आदमी हो या राजनीतिक दल उसे हकीकत का पता नहीं चलता है।अहंकार उसे बड़ा न होने पर भी बड़ा होने का भ्रम पैदा करता रहता है। टकराव की स्थिति बनाता है।टकराव से नुकसान ही होता है।आपसी समझबूझ से जो बात बन सकती है,अहंकार के कारण वह बात बिगड़ जाती है और दोनों पक्ष खुद को बड़ा मानकर दूसरे पक्ष को छोटा बताने का प्रयास करने लग जाते हैं। बड़ा होने के कारण दोनों बड़ा हिस्सा चाहते है। यूपी में सपा व कांग्रेस के बीच यही चल रहा है।कांग्रेस हकीकत में यूपी में बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई है।उसे चुनाव में दो प्रतिशत वोट मिले हैं।वह पिछले विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर लड़ी थी,उसमें से दो सीटें जीती थीं।चार पर दूसरे नंबर पर रहीं थी और २०सीटों पर कुछ हजार वोट मिले थे।यह हकीकत है और इसे भूलकर कांग्रेस ने पहले १८१ सीटों की सूची सपा को सौंपी थी.उसके बाद चर्चा रही कि १२६ सीटों की सूची सपा को सौंपी गई है।सपा कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें देने के पक्ष में शुरू से नहीं है।

कांग्रेस का मानना है उसे २७ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीटें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीती गई सीटों के हिसाब से मिलनी चाहिए।कांग्रेस लोकसभा में कुछ सीटों पर जीत को अपनी जीत मानती है यानी कि लोगों ने कांग्रेस को वोट देकर जिताया है। जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मानना है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें जीती हैं,वह सपा के कारण जीती हैं। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो इतनी सीटें नहीं जीत पातीं।सपा चाहती है कि कांग्रेस को यूपी मे अपनी स्थिति को देखते हुए ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए नहीं मांगना चाहिए।उसे तो उतनी ही सीटों पर खुश रहना चाहिए जितनी सीटें सपा उनको खुशी खुशी दे रही हैं। सपा यूपी में बड़े भाई की भूमिका में तो रहना ही चाहती है,साथ ही वह यह भी चाहती है कि बड़े भाई के नाते वह जो फैसला करे उसे कांग्रेस को मानना चाहिए। बताया जाता है कि अखिलेश जब दिल्ली गए थे तो वह राहुल गांधी से यूपी में सीट बंटवारे पर बात करना चाहते थे,उन्होंने बात भी तो राहुल गांधी ने उनसे कह दिया था कि कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर बात करने के लिए समिति गठित कर दी है,आपको समिति से बात करनी चाहिए।बताया जाता है कि यह बात अखिलेश को बुरी लगी कि वह राहुल गांधी के साथ मिलकर सीटों पर बात करना चाहते थे और राहुल गांधी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया।इस पर अखिलेश ने यूपी लौटकर सपा की समिति गठित की और दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर पहले दौर की बैठक हुई तो उसमें सपा की तरफ से महासचिव रामगोपाल यादव ने कांग्रेस को २६ सीटें आफर की और पांच सीटों पर सपा के प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी गई।यह राहुल गांधी के अखिलेश से सीटों पर बात न करने का परिणाम माना जा रहा है। राहुल गांधी व अखिलेश के बीच बात होती तो सीटों की संख्या कुछ बढ़ सकती थी लेकिन जब समितियों के बीच बात हो रही है तो समितियां तो जीती व हारी सीटों पर बात करके फैसला करेंगी और वही हुआ है. कांग्रेस ने पिछली बार जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था,उतनी सीटों का आफर कर दिया गया है। यानी कांग्रेस ने अखिलेश के इगो को हर्ट किया तो बदले में सपा ने कांग्रेस के इगो को हर्ट कर जवाब दे दिया है कि बड़े भाई हम है तो हम ही फैसला करेंगे और तुम छोटे भाई हो तो मांगो मत हम जो दे रहे हैं, वही काफी हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें सहारनपुर और बेहट सीटें भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पांच उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बातचीत के दो दौर के बाद, सपा ने कांग्रेस को उन सीटों में से 26 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है, जिन्हें कांग्रेस ने प्राथमिकता दी थी। हालाँकि, गठबंधन की पूरी रूपरेखा अभी तय होनी बाकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे और बातचीत करने की बात कही है। उनका तर्क है कि सीटों का बंटवारा केवल निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के आधार पर नहीं, बल्कि चुनावी संभावनाओं और जनता की उम्मीदों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर सकती है।अभी कांग्रेस सपा के बीच सबकुछ खत्म नहीं हुआ है। यह तो दोनों तरफ से झुकने व झुकाने का खेल है, दोनों एक दूसरे को झुकाने का प्रयास आखिरी तक करेंगे।कांग्रेस की कोशिश है कि उसे पिछली बार से ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिलनी चाहिए।वही अखिलेश यादव का मानना है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की जगह उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जितनी सीटों पर वह जीत सकती हैं।

विश्लेषण

ना बात, ना मुलाकात, भारत से 'खाली हाथ' लौटे पाक मंत्री

स्वदेश कुमार ,लखनऊ



दक्षिण एशिया की कूटनीति और भारतीय राजनीति में तीन दिनों तक चली सरगर्मी के बाद पाकिस्तान के संघीय जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण समन्वय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक का बहुचर्चित भारत दौरा समाप्त हो गया है। 20 से 22 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यतागत संवाद फोरम में शिरकत करने के बाद वे स्वदेश लौट चुके हैं। लेकिन भारत में उन्हें कोई अहमियत नहीं दी गई। मई 2023 में तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के गोवा दौरे के तीन साल से अधिक समय बाद यह पहला मौका था, जब पाकिस्तान का कोई कैबिनेट मंत्री भारत की धरती पर पहुंचा था। लेकिन इस यात्रा की सबसे बड़ी संवेदनशीलता केवल तीन साल के अंतराल से नहीं जुड़ी थी, बल्कि इसका सीधा संबंध अप्रैल 2025 के भयावह पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत द्वारा चलाए गए चार दिवसीय सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे गहरे तनाव और युद्ध जैसे हालात से था। अब जब यह दौरा खत्म हो चुका है, तो यह साफ हो गया है कि इस यात्रा ने दोनों देशों के जमे हुए रिश्तों की बर्फ तो नहीं पिघलाई, लेकिन भारत की सख्त कूटनीतिक लकीर और घरेलू राजनीति के वैचारिक द्वंद्व को पूरी तरह उजागर कर दिया है।

इस पूरे तीन दिवसीय दौरे के दौरान भारत सरकार अपने उस पुराने और अडिग रुख पर चट्टान की तरह कायम रही कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते और खून व पानी एक साथ नहीं बह सकते। नई दिल्ली ने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि मुसादिक मलिक का यह दौरा विशुद्ध रूप से एक बहुपक्षीय मंच के अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का हिस्सा था। चूंकि भारत इस फोरम का मेजबान था जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में की थी इसलिए संगठन के चार्टर के तहत सभी 10 सदस्य देशों, पर्यवेक्षकों और संवाद साझेदारों को निमंत्रण भेजना भारत की कूटनीतिक बाध्यता थी। यही वजह रही कि तीन दिनों तक दिल्ली में रहने के बावजूद मुसादिक मलिक और भारत सरकार के किसी भी प्रतिनिधि के बीच कोई 'फेस टू फेस' यानी द्विपक्षीय मुलाकात या औपचारिक वार्ता नहीं हुई। इसके विपरीत, मलिक की मौजूदगी के बीच ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में दोहराया कि पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा और जनभावनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जाने के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया, हालांकि उन्हें आगरा के ताजमहल, हुमायूं के मकबरे, किला राय पिथौरा और दिल्ली हाट जैसे चुनिंदा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थलों के भ्रमण की अनुमति दी गई।

दौरे के समापन के साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तानी मंत्री की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की कोशिशें भारत की सख्त घेराबंदी के सामने बेअसर रहीं। पुराना किला के मंच से मुसादिक मलिक ने हुमायूं और शेरशाह सूरी का उदाहरण देते हुए 'एक किला, दो प्रतिद्वंद्वी' जैसी प्रतीकात्मक बातें कहीं और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे आसान मुद्दों से संवाद शुरू करने की पैरवी की। लेकिन जब भारतीय मीडिया ने उनसे सीमा पार आतंकवाद और कुछ महीने पहले सिंधु जल संधि पर दी गई उनकी खुद की 'हाथ काट देने' वाली धमकी पर तीखे सवाल पूछे, तो वे कूटनीतिक चुप्पी साधते और सबूतों की मांग करते हुए बचते नजर आए। अगले साल 2027 में पाकिस्तान में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय नेतृत्व के शामिल होने की उम्मीद जताते हुए भी वे अपने देश लौट गए, लेकिन दिल्ली से उन्हें द्विपक्षीय संबंधों में नरमी का कोई संकेत नहीं मिला।

हालांकि, इस तनावपूर्ण माहौल और कड़े सरकारी प्रतिबंधों के बीच भी देश के कुछ हिस्सों से इस यात्रा के स्वागत और समर्थन के स्वर सुनाई दिए। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने मुसादिक मलिक के भारत आगमन का खुले दिल से स्वागत करते हुए इसे एक "मुबारक" कदम बताया और उम्मीद जताई कि यह दौरा दोनों पड़ोसी देशों के बीच संवाद की एक नई शुरुआत साबित होगा। कश्मीर की मुख्यधारा की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दलों का हमेशा से यह मानना रहा है कि सीमा पर तनाव और युद्ध के हालात का सबसे सीधा और दर्दनाक असर जम्मू-कश्मीर की जनता को झेलना पड़ता है, इसलिए बहुपक्षीय मंचों पर होने वाली ऐसी मुलाकातों को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए।

दूसरी तरफ, दिल्ली के सियासी गलियारों में इस पूरे दौरे के दौरान और इसके खत्म होने के बाद भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य गैर-भाजपा दलों की सोच बेहद आक्रामक और आलोचनात्मक रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप में घेरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, सांसद मनीष तिवारी, सुप्रिया श्रीनेत और इमरान मसूद शामिल हैं, ने सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठाए। विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर रही कि भारत ने संस्कृति मंत्री को निमंत्रण भेजा था, लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर मुसादिक मलिक को भेजा वही नेता जिन्होंने सिंधु जल संधि के निलंबन पर भारत को धमकाया था। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और मुसादिक मलिक की एक ही मंच पर मौजूदगी की तस्वीरों पर तंज कसते हुए कहा कि जो भाजपा कल तक आतंकवाद और बातचीत साथ न चलने की कसमें खाती थी, वह आज भारत को धमकाने वाले पाकिस्तानी मंत्री की मेजबानी कर रही है और उन्हें ताजमहल घुमाने की अनुमति दे रही है। शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसे बेहद दुखद और शर्मनाक करार देते हुए कहा कि सरकार ने देश की जनता से किए अपने वादे के विपरीत जाकर पाकिस्तान के प्रति नरम रुख दिखाया है। विपक्ष के इस रुख के पीछे केवल तात्कालिक विरोध नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति का एक पुराना इतिहास और वैचारिक द्वंद्व छिपा है। जब 2004 से 2014 के बीच केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ संवाद या 2009 में शर्म अल-शेख जैसे मंचों पर बातचीत करते थे, तब तत्कालीन विपक्षी दल भाजपा और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी उन पर कमजोर विदेश नीति और बिरयानी कूटनीति का आरोप लगाते थे। 2014 के बाद जब सत्ता बदली, तो विपक्ष ने भी उसी भाषा और उन्हीं पैमानों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी अचानक नवाज शरीफ के जन्मदिन पर लाहौर पहुंचे थे, तब भी कांग्रेस ने इसे शहीदों का अपमान बताया था। इसी तरह, मई 2023 में जब बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में आए थे, तब तत्कालीन विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उन्हें आतंकवाद का प्रवक्ता कहकर कड़ा संदेश दिया था, लेकिन विपक्ष ने उस समय भी पाकिस्तान को बुलाने पर सवाल उठाए थे। हालांकि, कांग्रेस के भीतर भी इस मुद्दे पर कूटनीतिक समझ रखने वाले नेताओं के बयानों में एक बारीक संतुलन देखने को मिला। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी ने यह स्वीकार किया कि एससीओ एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है और मेजबान होने के नाते भारत के लिए सभी सदस्यों को बुलाना एक बाध्यता है, इसलिए इसे द्विपक्षीय दोस्ती नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान द्वारा मुसादिक मलिक जैसे भारत-विरोधी बयान देने वाले व्यक्ति को चुनना यह दर्शाता है कि इस्लामाबाद की 'हजार घाव देकर भारत को लहूलुहान करने' की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। मुसादिक मलिक के दौरे के समापन के साथ अब यह तस्वीर पूरी तरह साफ है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में बहुपक्षीय मंचों की मर्यादा निभाते हुए पाकिस्तान को अलग-थलग रखने और द्विपक्षीय वार्ता न करने की अपनी शर्त पर अडिग है, तो वहीं घरेलू राजनीति में यह तीन दिवसीय घटनाक्रम सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राष्ट्रवाद और विदेश नीति की कसौटियों पर एक-दूसरे को घेरने का एक नया अध्याय जोड़ गया है।

राशिफल

मेष राशिः आज कुछ खुशियां तो कुछ चिंताएं मिल सकती हैं। दूर के रिश्तेदार से कोई अप्रिय खबर मिलने की आशंका है। कारोबार में नई साझेदारी का अवसर मिलेगा और पुरानी योजनाओं से लाभ हो सकता है। बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें। मौसम के बदलाव से सेहत प्रभावित हो सकती है। परिवार और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।

वृषभ राशिः घर-परिवार में उत्साह और खुशियों का माहौल रहेगा। किसी मांगलिक कार्य की तैयारी हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों के काम से बॉस प्रभावित होंगे। बैंकिंग और वित्त क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है।

मिथुन राशिः वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी बात किसी को बुरी लग सकती है। घर में मेहमान के आगमन से खुशी मिलेगी। अचानक धन लाभ के योग हैं। निजी जानकारी साझा करने से बचें। कारोबार में बदलाव या नई रणनीति बनाने का विचार सफल हो सकता है।

कर्क राशिः हर काम सावधानी से करें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें। संतान के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे। पुराने प्रेम संबंध से जुड़े व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे वर्तमान रिश्तों में तनाव आए।

सिंह राशिः विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे परिणाम की खबर मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों के काम और सुझावों की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार से सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। अपनी कमजोरियों को पहचानकर सुधार करें। दूसरों के विवादों में पड़ने से बचें।

कन्या राशिः उन्नति के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को योग्यता के अनुसार मौका मिलेगा। घर के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। पारिवारिक मनमुटाव दूर करने में आपकी भूमिका अहम रहेगी। रिश्तेदारों के यहां जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

तुला राशिः मेहनत और कार्यकुशलता से पहचान बनेगी। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा। संतान की ओर से अच्छी खबर आएगी। ऑनलाइन खरीदारी में सावधानी रखें और बच्चों की सेहत पर ध्यान दें।

वृश्चिक राशिः आर्थिक लाभ और नए अवसर मिलने के योग हैं। नए लोगों से संपर्क भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है। कारोबार में मुनाफा मिलेगा और जरूरत के समय आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सकती है। संतान के लिए वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। खर्चों में बजट का ध्यान रखें।

धनु राशिः भागदौड़ और व्यस्तता बनी रहेगी। आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाशेंगे। संतान की पढ़ाई या विशेष कोर्स के लिए बाहर जाने की योजना बन सकती है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। सेहत की अनदेखी न करें। ऑफिस में लापरवाही से बॉस नाराज हो सकते हैं।

मकर राशिः एक साथ कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन समझदारी से उन्हें पूरा कर लेंगे। नए काम की शुरुआत में परिवार का सहयोग मिलेगा। पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। लंबी यात्रा फिलहाल टालना बेहतर होगा। भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लें, लाभ मिल सकता है।

कुंभ राशिः सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। मेहनत से महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। यात्रा के दौरान उपयोगी जानकारी मिल सकती है। पुराने अटके काम में गति आएगी। किसी को उधार देने से पहले सोच-विचार करें। घर में धार्मिक या शुभ कार्यक्रम होने के संकेत हैं।

मीन राशिः आज धैर्य और समझदारी से काम लें। जीवनसाथी से बातचीत में संयम रखें और उनकी भावनाओं का ध्यान दें। संतान की संगति और व्यवहार पर नजर रखें। दूसरों के बहकावे में आकर फैसला न लें। पारिवारिक समस्याओं को आपसी बातचीत से सुलझाएं और बाहरी दखलंदाजी से बचें।

राजनीति

यूपी में नया साल चुनावी बिगुल के साथ देगा दस्तक

अजय कुमार,

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने की आहट के साथ ही पूरे प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।



नेता टिकट के लिए दौड़ लगा रहे हैं, तो योगी सरकार अपने मनपसंद अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लगी है। आचार संहिता लगने से पूर्व सरकार विकास की किसी योजना को भी मंजूरी देने और नई योजनाओं का उद्घाटन करने में लगी है। प्रदेश में आचार संहिता लगने के लिए दो महीने से भी कम का समय बाकी रह गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि नया साल और आचार संहिता एक साथ 'दस्तक' देंगे। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्येक चुनाव से पूर्व आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल 19 मार्च 2027 को समाप्त होने जा रहा है। संवैधानिक नियमों के तहत निर्वाचन आयोग किसी भी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले तक की अवधि में कभी भी चुनाव करा सकता है। निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक 2027 के चुनावों की आधिकारिक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पिछले चुनावी चक्रों और उपलब्ध जानकारियों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मतदान फरवरी या मार्च 2027 में हो सकता है। इसके लिए नए साल के दूसरे हफ्ते तक आचार संहिता लागू हो सकती है। साल 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने 8 जनवरी 2022 को कार्यक्रम की घोषणा की थी और उसी दिन से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई थी। इसी पैटर्न को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि 2027 के चुनावों के लिए भी जनवरी 2027 के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो सकती है। जब तक आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक इन तारीखों को संभावित ही माना जाता है।

आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही प्रदेश की पूरी शासन व्यवस्था और सरकारी कामकाज के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव आ जाता है। चूंकि आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना है, इसलिए सत्ताधारी दल के हाथों से प्रशासनिक मशीनरी के इस्तेमाल का अधिकार सीमित हो जाता है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद राज्य का पूरा प्रशासनिक तंत्र, विशेष रूप से चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी और पुलिस बल, सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और निगरानी में आ जाते हैं। इसके बाद सरकार कोई भी नया नीतिगत फैसला नहीं ले सकती और न ही किसी नई कल्याणकारी योजना, परियोजना या वित्तीय अनुदान की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री, मंत्री या किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए नए कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण या भूमि पूजन करने पर पूरी तरह से रोक लग जाती है। सरकारी खजाने से सरकार की उपलब्धियों का बखान करने वाले विज्ञापनों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यहां तक कि सरकारी वेबसाइटों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों से मंत्रियों और नेताओं की तस्वीरें,



पोस्टर और बैनर तय समय सीमा के भीतर हटा दिए जाते हैं। सरकारी संपत्तियों से प्रचार सामग्री हटाने के लिए 24 घंटे, सार्वजनिक स्थानों के लिए 48 घंटे और निजी संपत्तियों के लिए 72 घंटे की समय सीमा निर्धारित होती है। सरकारी कामकाज पर इसका एक और बड़ा असर तबादलों और नियुक्तियों के रूप में दिखता है। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला या नई तैनाती बिना चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के नहीं की जा सकती। मंत्रियों के सरकारी वाहनों और गेस्ट हाउस के इस्तेमाल पर भी सख्त पाबंदी लग जाती है। कोई भी मंत्री अपने सरकारी दौरे को चुनाव प्रचार के साथ नहीं जोड़ सकता और न ही सरकारी कर्मचारियों या संसाधनों का उपयोग चुनावी सभाओं के लिए कर सकता है। हालांकि, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि प्रदेश में विकास कार्य या रोजमर्रा के सरकारी काम पूरी तरह ठप हो जाते हैं। जो परियोजनाएं आचार संहिता लगने से पहले ही धरातल पर शुरू हो चुकी हैं, उनका निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। इसी तरह, पहले से चल रही पेंशन, राशन वितरण, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन स्थिति में राहत पहुंचाने जैसे नियमित प्रशासनिक कार्यों पर कोई रोक नहीं होती। सरकार केवल रूटीन के कामकाज ही निपटा सकती है, लेकिन किसी नए वर्ग को लुभाने वाला कोई फैसला नहीं ले सकती।

चुनावी बिगुल बजने और आचार संहिता लागू होने की इस समय सीमा को भांपते हुए हर सरकार उससे ठीक पहले के महीनों और हफ्तों में बेहद सक्रिय हो जाती है। आचार संहिता लगने से पहले सरकार की कोशिश होती है कि वह अपने सभी प्रमुख चुनावी वादों को पूरा कर दे और जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाले बड़े फैसले ले ले, ताकि चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ मिल सके। इस कड़ी में सबसे पहला और अहम कदम बड़ी विकास परियोजनाओं के ताबड़तोड़ शिलान्यास और लोकार्पण का होता है। एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, हवाई अड्डे और बड़े पुलों जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन आनन-फानन में किया जाता है, ताकि काम शुरू होने या पूरा होने का श्रेय लिया जा सके। इसके साथ ही, राज्य कैबिनेट की लगातार बैठकें बुलाकर विभिन्न वर्गों को खुश करने वाली नई योजनाओं को मंजूरी दी जाती है। इनमें किसानों के लिए ऋण माफी या सम्मान निधि में बढ़ोतरी, युवाओं को मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन या लैपटॉप वितरण, बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता जैसी लोकलुभावन घोषणाएं शामिल होती हैं। यह कार्य योगी सरकार भी कर रही है और पूर्ववर्ती सरकारें भी करती रही हैं।

प्रशासनिक स्तर पर आचार संहिता लगने से ठीक पहले बड़े पैमाने पर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। सरकार अपनी सुविधा और प्रशासनिक चुस्ती के हिसाब से जिलों में जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की तैनाती करती है, क्योंकि एक बार आचार संहिता लागू होने के बाद तबादलों की चाबी चुनाव आयोग के पास चली जाती है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के बड़े वोट बैंक को साधने के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, बोनस की घोषणा, पदोन्नति और नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने जैसे फैसले भी इसी दौर में लिए जाते हैं। कई बार सरकार विभिन्न आयोगों, बोर्डों और निगमों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां भी आचार संहिता लगने से ऐन पहले कर देती है, ताकि सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जा सके। इसी तरह, किसी क्षेत्र विशेष की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए नई तहसील, ब्लॉक या नगर पंचायत के गठन और किसी स्थान या संस्थान के नाम परिवर्तन जैसे फैसले भी कैबिनेट से पास कराए जाते हैं। कुल मिलाकर, आचार संहिता लागू होने से पहले का समय सरकार के लिए अपने तरकश के सभी तीर चलाने का होता है, जबकि आचार संहिता लागू होने के बाद पूरा तंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी में जुट जाता है।

एक नजर

किसान यूनियन ने धान खरीदी की मात्रा बढ़ाने, टोकन में राहत देने सौंपा ज्ञापन

कांकेर, 27 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। जिले में धान खरीदी के बीच आज गुरूवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने जिला प्रशासन के सामने तीन मांगें रखी हैं। यूनियन के जिला अध्यक्ष बाबूलाल साहू के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें फसल बीमा की राशि कटौती में पारदर्शिता लाने, धान खरीदी की मात्रा बढ़ाने और ऑनलाइन-ऑफलाइन टोकन व्यवस्था में किसानों को राहत देने की मांग की गई है। किसान यूनियन का आरोप है कि फसल बीमा के नाम पर उनके खातों से राशि तो काट ली जाती है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। वहीं धान खरीदी केंद्रों में कम मात्रा में खरीदी और अन्य अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान यूनियन ने यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि कई खरीदी केंद्रों में प्रतिदिन लगभग 450 क्विंटल ही धान खरीदा जा रहा है। इसके चलते किसानों का धान समय पर नहीं बिक पा रहा है। मौसम खराब होने और बारिश के कारण खरीदी प्रभावित होने से किसानों की परेशानी और बढ़ जाती है। इसके अलावा धान में नमी और सुखत के नाम पर अधिक कटौती तथा कुछ केंद्रों में पैसे की मांग किए जाने की शिकायतें भी उठाई गई हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन व्यवस्था में किसानों को सुविधा देने की तीसरी मांग है। किसान यूनियन ने बताया कि सरकार की ओर से 70 और 30 प्रतिशत का अनुपात निर्धारित किया गया है, लेकिन कई किसान ऑनलाइन प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं। ऐसे में किसानों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन व्यवस्था में समान रूप से 50-50 प्रतिशत की सुविधा देने की मांग की, ताकि अशिक्षित और तकनीकी जानकारी नहीं रखने वाले किसानों को भी धान बेचने में परेशानी न हो। उन्होंने बीमा राशि की कटौती का सालाना रिकॉर्ड किसानों को उपलब्ध कराने और बीमा क्लेम की प्रक्रिया सरल बनाने की भी मांग की है।

एनएसएल कोक ओवन ने 5 मिलियन टन कोक उत्पादन का आंकड़ा पार किया

जगदलपुर, 27 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। NMDC स्टील लिमिटेड के नगरनार स्टील प्लांट ने 25 नवंबर 2026 को 5 मिलियन टन कोक उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया। यह वह कुल मात्रा है, जिसका उत्पादन कोक ओवन बैटरी द्वारा इसकी शुरुआत से लेकर अब तक किया गया है। गौरतलब है कि NSL की कोक ओवन बैटरी नंबर 1 को 28 अक्टूबर 2022 को कार्यरत किया गया था । कोक ओवन बैटरी सबसे पहले शुरू होने वाली इकाइयों में से एक थी। इसके बाद, 25 अप्रैल 2023 को हस्रु की बैटरी नंबर 2 भी कार्यरत हो गई। NSL के कोक ओवन की कुशल कार्यप्रणाली, लागत को नियंत्रित रखने और कंपनी को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में काफी मदद करती है। महाप्रबंधक एवं संचार प्रमुख, रफीक़ अद्वहमद जिनाबड़े ने बताया कि NSL के ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल कोक ओवन में 67 ओवन वाली 2 बैटरिय ं हैं। इनमें से प्रत्येक ओवन 7 मीटर ऊंचा है और ये चौबीसों घंटे कच्चे कोयले को मेटलर्जिकल कोक में बदलते हैं, जिसका इस्तेमाल 3 मिलियन टन क्षमता वाली ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। हस्रु के कोक ओवन की एक खास खूबी इसका पर्यावरण के अनुकूल CDCP (कोक ड्राई कूलिंग प्लांट) है। CDCP में गर्म कोक को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करने के बजाय, अक्रिय नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में निकलने वाली गर्मी (वेस्ट हीट) को कैप्चर करके बिजली बनाई जाती है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कोयले की धूल से पर्या वरण प्रदू षित न हो।

कोक कूलिंग कोल का उपयोग किसी भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में स्टील बनाने की प्रक्रिया में ईंधन की तरह होता है। कोकि ंग कोल के जलने से वह अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, जो आयरन ओर को पिघलाने के लिए जरूरी है। इस से पिघली हुई धातु या पिग आयरन प्राप्त होता है। चूँ कि कच्चा कोयला आयरन ओर के वजन के नीचे दबकर टूट सकता है और अशुद्धियां छोड़ सकता है, इसलिए कोक ओवन प्लांट में कोयले को सख्त और छिद्रपूर्ण 'मेटलर्जिकल कोक' (धातु- शोधन कोक) में बदल दिया जाता है।

बाल गृह में उत्साहपूर्वक मनाया गया संविधान दिवस, बच्चों ने किया संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

जगदलपुर 27 नवंबर। संविधान दिवस के अवसर पर बाल गृह, जगदलपुर में विविध जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बाल गृह में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले निवासरत बच्चों ने भारतीय संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को भारतीय संविधान के महत्व, उसके मूल सिद्धांतों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी दी गई।कार्यक्रम में बच्चों को संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के मूल आदर्शों के साथ-साथ मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के संबंध में विस्तार से बताया गया। शिक्षकों ने संविधान



निर्माण की ऐतिहासिक प्रक्रिया, संविधान सभा के सदस्यों तथा उनके महत्वपूर्ण योगदान से बच्चों को परिचित कराया। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा तथा संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हुआ।

इस अवसर पर बस्तर के ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख करते हुए बताया गया कि बस्तर (कांकेर रियासत) से डॉ. ठाकुर रामप्रसाद पोटाई भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। यह क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है।

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र पाणिग्राही ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक राष्ट्र की आत्मा और सामाजिक समरसता का आधार है।

उन्होंने कहा कि बच्चों को बचपन से ही संविधान के मूल्यों और अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों की जानकारी होना आवश्यक है। विशेषकर देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा समान अधिकारों, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और विकास के अवसरों का हकदार है। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना केवल शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। श्री पाणिग्राही ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे संविधान में दिए गए आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें तथा एक जिम्मेदार, जागरूक और संवेदनशील नागरिक बनने का संकल्प लें।

कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में संविधान के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक चेतना, समानता, सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना रहा। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के सदस्य धनेश्वरी वर्मा, महेश्वरी सरवन, रंजीता जोशी, सुनीता देवांगन, सोमा सरकार, सरिता दुबे, सतनी दास, करन यादव सहित बाल गृह के बच्चों उपस्थित थे।

जिला स्तरीय बस्तर ओलम्पिक में जगदलपुर 115 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बना

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

जगदलपुर, 27 नवंबर। इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम जगदलपुर में आयोजित जिला स्तरीय बस्तर ओलम्पिक 2026 प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। दो दिवसीय मुकाबलों में जगदलपुर विकासखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 115 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, जबकि लोहंडीगुड़ा 55 अंकों के साथ रनर-अप रहा ।

जगदलपुर ने 30 प्रथम, 7 द्वितीय और 4 तृतीय स्थानों (कुल 41) के साथ तालिका में एकतरफा बढ़त बनाए रखी। दूसरे स्थान पर रहे लोहंडीगुड़ा ने 8 प्रथम, 10 द्वितीय और 4 तृतीय स्थानों (कुल 22) के साथ 55 अंक प्राप्त किए। तीसरे स्थान के कड़े मुकाबले में बकावंड ने 4 प्रथम, 4 द्वितीय और 8 तृतीय स्थानों (कुल 16) के साथ 33 अंक जुटाए। जबकि बस्तर विकासखंड 1 प्रथम, 7 द्वितीय और 6 तृतीय स्थानों (कुल 14) के साथ 31 अंकों पर चौथे स्थान पर रहा। अन्य विकासखंडों में बास्तानार 1 प्रथम,



10 द्वितीय और 6 तृतीय स्थानों (कुल 17) के साथ 29 अंक लेकर पांचवें, तोकापाल 5 प्रथम, 2 द्वितीय और 4 तृतीय स्थानों (कुल 11) के साथ 25 अंक लेकर छठे तथा दरभा 1 प्रथम, 2 द्वितीय और 2 तृतीय स्थानों (कुल 5) के साथ 11 अंक अर्जित कर सातवें स्थान पर रहा।

जिला स्तरीय बस्तर ओलम्पिक के समापन अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह आयोजन युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर है। जोन और ब्लॉक स्तर से होते हुए जिला स्तर तक पहुंचे प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया तथा अपील की कि खिलाड़ी इस मंच का भरपूर लाभ उठाएं, खेल के माध्यम से आगे बढ़ें और साथ ही शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दें।

इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी ने बताया कि यह बस्तर ओलम्पिक का तृतीय वर्ष है। उन्होंने कहा कि खेल के साथ-साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना आवश्यक है और सरकार विद्यार्थियों व खिलाड़ियों के लिए स्कूल, रहने की व्यवस्था तथा आश्रम-छात्रावास जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। पहले माओवाद समस्या के कारण अंदरूनी क्षेत्रों के बच्चों को मुख्यालयों तक पहुंचने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब सड़क, पुल-पुलियों के निर्माण और सुविधाओं से उन्हें मुख्यधारा में लाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर जिला पंचायत खेल एवं युवा कल्याण समिति के सभापति बनवासी मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर के युवाओं को प्रतिभा दिखाने के लिए शानदार मंच और नई दिशा मिली है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बस्तर जिले से एक लाख 8 हजार पंजीयन होना युवाओं के बढ़ते उत्साह को दर्शाता है। स्वागत उद्बोधन अपर कलेक्टर सीपी बघेल द्वारा दिया गया। समारोह में नगर निगम सभापति खेमसिंह देवांगन, जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान कश्यप व पद्मिनी कश्यप, एमआईसी सदस्य सुरेश गुप्ता, निर्मल पाणिग्रही व अन्य जनप्रतिनिधि समेत नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री अंशिका जैन, खेल विभाग के सहायक संचालक सुशांत पॉल और बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे।

पीएम सूर्य घर योजना से कमल सेठिया का घर रोशन हुआ सौर ऊर्जा से, बिजली बिल में मिलेगी बड़ी राहत



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 27 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा का सशक्त माध्यम बन रही है। योजना के माध्यम से जिले के नागरिक अपने घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर बिजली खर्च में कमी लाने के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में स्कूल पारा निवासी कमल सेठिया ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ लेते हुए अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराया है। उन्होंने बताया कि योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया। सोलर पैनल स्थापित होने से अब घर में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। इससे परंपरागत बिजली पर निर्भरता कम होगी और हर महीने आने वाले बिजली बिल में भी राहत मिलेगी। कमल सेठिया ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आम परिवारों के लिए काफी लाभदायक है। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी से सोलर पैनल लगवाना पहले की तुलना में आसान हुआ है। उन्होंने योजना को घरों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम नागरिकों को आर्थिक रूप से राहत पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जिले के अन्य नागरिकों से भी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ उठाने और सौर ऊर्जा अपनाने की अपील की।

गीदम में अवैध धान भंडारण पर प्रशासन ने 3 व्यापारियों से 100 क्विंटल धान जब्त किया

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 27 नवंबर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने गीदम में सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर 25 नवंबर को गीदम के व्यापारियों के गोदामों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें तीन व्यापारियों से कुल 200 बोरी, करीब 100 क्विंटल धान जप्त किया गया।

खाद्य अधिकारी वेणुका ध्रुव एवं सहायक खाद्य अधिकारी प्रीति पाण्डेय के मार्गदर्शन में गठित संयुक्त जांच दल ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों और गोदामों में स्टॉक व दस्तावेजों की जांच की। जांच में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

किससे कितना धान जब्त हुआ

- मेसर्स पवन ट्रेडर्स, गीदम : 110 बोरी, 55 क्विंटल
- मेसर्स शिवहरे ब्रदर्स : 50 बोरी, 25 क्विंटल
- मेसर्स गणेश ट्रेडर्स : 40 बोरी, 20 क्विंटल



कार्रवाई के दौरान खाद्य निरीक्षक प्रमोद कुमार सोनवानी, खाद्य निरीक्षक हिमांशु केशरवानी, मंडी सचिव गीदम एमएस मण्डावी एवं मंडी उपनिरीक्षक बालमुकुंद यादव मौजूद रहे। जप्त धान के संबंध में प्रकरण आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए कलेक्टर, खाद्य शाखा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

जिला प्रशासन ने बताया कि उपार्जन केंद्रों पर पंजीकृत किसानों से सहकारी समितियों के माध्यम से औसत अच्छी गुणवत्ता, एफएक्यू का धान खरीदा जा रहा है। अमानक धान पाए जाने पर उसे अस्वीकृत कर किसानों को निर्धारित गुणवत्ता का धान लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रत्येक उपार्जन केंद्र में निगरानी समिति गठित की गई है और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए नोडल अधिकारी तथा ट्रस्टेड पर्सन की नियुक्ति भी की गई है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को धान खरीदी व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने तथा अवैध भंडारण और अनियमितता पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण और निगरानी की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सूचना पर प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह

कांकेर 27 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। जिले के कोयलीबेड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम छोटेबेठिया में प्रशासन की तत्परता से एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह रुकवाया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर मिली सूचना के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर विवाह की तैयारियों को रुकवाने की कार्रवाई की। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री समीर पाण्डेय ने बताया कि पखांजूर क्षेत्र के ग्राम छोटेबेठिया में आगामी 26 दिसंबर 2026 को नाबालिग बालिका का विवाह निर्धारित था। इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग कांकेर को मिली। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के आदेशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर विभाग द्वारा संयुक्त टीम गठित की गई, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, थाना छोटेबेठिया पुलिस एवं ग्राम पंचायत सचिव शामिल थे।

एसएसआर-2026 के तहत राजनीतिक दलों की द्वितीय साप्ताहिक बैठक में दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया बताई गई



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 27 नवंबर। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसएसआर-2026 कार्यक्रम के तहत आज संयुक्त जिला कार्यालय दंतेवाड़ा के भू-तल स्थित सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की द्वितीय साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दंतेवाड़ा ने उपस्थित प्रतिनिधियों को निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, विलोपित करने तथा संशोधन से संबंधित दावे एवं आपत्तियों की प्राप्ति और उनके निराकरण की प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। प्रक्रिया में पारदर्शिता और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में भी अवगत कराया गया।

बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्ररूप-9, 10, 11, 11ए एवं 11बी की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई गई।

अब तक 479 आवेदन प्राप्त

अधिकारियों ने बताया कि 26 नवंबर 2026 की स्थिति में प्राप्त आवेदनों का विवरण इस प्रकार है : - प्ररूप-6, नाम जोड़ने के लिए : 128 आवेदन - प्ररूप-7, नाम विलोपित करने के लिए : 63 आवेदन - प्ररूप-8, संशोधन एवं अन्य प्रविष्टियों के लिए : 288 आवेदन - कुल आवेदन : 479

बैठक में प्राप्त आवेदनों की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्वाचक नामावली को अद्यतन, त्रुटिरहित एवं अधिक समावेशी बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे और निर्वाचन प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

बस्तर ओलंपिक भाजपा नेताओं का पोस्टर ओलंपिक साबित हुआ:राजेश चौधरी

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

जगदलपुर, 27 नवंबर। नगर पालिक निगम जगदलपुर के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने बस्तर ओलंपिक के आयोजन को लेकर भाजपा सरकार एवं जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने बस्तर ओलंपिक को खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और बस्तर की संस्कृति एवं खेल परंपराओं को सम्मान देने का मंच बनाने के बजाय भाजपा नेताओं के प्रचार-प्रसार और राजनीतिक महिमामंडन का माध्यम बना दिया है। जिस आयोजन का उद्देश्य बस्तर के खिलाड़ियों को सम्मानजनक अवसर प्रदान करना होना चाहिए था, वह आज भाजपा नेताओं के पोस्टर और तस्वीरों से अपनी राजनीतिक पहचान बनाने का आयोजन बनकर रह गया है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बस्तर ओलंपिक नहीं, बल्कि भाजपा नेताओं का पोस्टर ओलंपिक साबित हुआ है।

राजेश चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर ओलंपिक के नाम पर बड़े-बड़े दावे करती है। सरकार मंचों से बस्तर के युवाओं, खिलाड़ियों और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें सम्मान देने तथा खेल के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की बातें करती है। लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो सरकार और प्रशासन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई देता है। बस्तर ओलंपिक के प्रचार-प्रसार के लिए लगाए गए बैनरों से बस्तर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित विधायक एवं वरिष्ठ आदिवासी नेता लखेश्वर बघेल की तस्वीर



गायब होना इसी मानसिकता को उजागर करता है।

उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक किसी राजनीतिक दल का निजी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह पूरे बस्तर संभाग का आयोजन है। इसमें संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से स्कूली बच्चे, युवा खिलाड़ी और ग्रामीण प्रतिभाएं हिस्सा लेते हैं। ऐसे आयोजन में सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को समान सम्मान और स्थान मिलना चाहिए। विधायक लखेश्वर बघेल केवल किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि बस्तर की जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। उनके क्षेत्र में आयोजित होने वाले संभागीय आयोजन के प्रचार बैनर से उनकी तस्वीर हटाना न केवल एक जनप्रतिनिधि का अपमान है, बल्कि उस क्षेत्र की जनता की जनभावनाओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी अपमान है।

राजेश चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के इशारे पर जिला प्रशासन बार-बार इस प्रकार की भेदभावपूर्ण कार्यशैली अपना रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन अपनी संवैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भूलकर भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। प्रशासन का दायित्व किसी राजनीतिक दल विशेष को खुश करना नहीं, बल्कि सभी जनप्रतिनिधियों के साथ निष्पक्षता, समानता और सम्मान का व्यवहार करना है। सरकारी आयोजन में राजनीतिक पक्षपात की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि बस्तर अपनी विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, सामाजिक सद्भावना और आपसी भाईचारे के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यहां के लोग राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर क्षेत्र के सम्मान और विकास के लिए एकजुट रहते हैं। लेकिन जब सरकारी आयोजनों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो इससे समाज में अनावश्यक असंतोष और अलगाव की भावना पैदा होती है। जिला प्रशासन की ऐसी कार्यशैली बस्तर की सामाजिक एकता और सद्भावना के लिए उचित नहीं है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि बस्तर ओलंपिक वास्तव में बस्तर के खिलाड़ियों और युवाओं का आयोजन है, तो फिर इसके प्रचार-प्रसार में केवल भाजपा नेताओं की तस्वीरों को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? क्या बस्तर के विकास, खेल और युवाओं के सम्मान का अधिकार केवल भाजपा नेताओं तक सीमित है? क्या विपक्ष के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को इसलिए नजरअंदाज किया जाएगा क्योंकि वे भाजपा से संबंधित नहीं हैं? प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किसके निर्देश पर इस प्रकार के भेदभावपूर्ण बैनर और पोस्टर तैयार किए जा रहे हैं।

राजेश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खेलों और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का हमेशा समर्थन करती रही है। बस्तर के युवा देश और प्रदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं, इसके लिए हर सकारात्मक पहल का स्वागत है। लेकिन खेल के नाम पर राजनीतिक भेदभाव, सरकारी संसाधनों का दलीय प्रचार के लिए इस्तेमाल और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा आयोजन से जुड़े संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन तत्काल इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे और सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति समान सम्मान सुनिश्चित करे। यदि इसके बावजूद सरकारी आयोजनों में राजनीतिक पक्षपात और जनप्रतिनिधियों के अपमान का सिलसिला जारी रहा तो कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बस्तर ओलंपिक के नाम पर लगाए गए बैनर-पोस्टरों में यदि राजनीतिक भेदभाव जारी रहा तो कांग्रेस पार्टी उन प्रचार सामग्रियों को हटाने और उनके विरोध में व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा संबंधित विभागों की होगी।

किसान 11 दिसंबर को करेंगे नेशलन हाइवे जाम

जगदलपुर, 27 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। बस्तर जिले में आई बाढ़ और बाढ़ से हुए हजारों हेक्टेयर फसल की बर्बादी को लेकर बस्तर के किसान आगामी 11 दिसंबर को नेशलन हाइवे जाम करने की चेतावनी दी है। यह निर्णय किसानों ने गुरूवार को बस्तर के मुरिया सदन में बैठक करके लिया है। लखेश्वर कश्यप ने कहा कि बस्तर के मुरिया सदन में किसानों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी 11 दिसम्बर को नेशनल हाइवे जाम किया जाएगा। इंद्रावती नदी बचाव संघर्ष समिति के संभागीय अध्यक्ष लखेश्वर कश्यप का कहना है कि किसानों की फसल बाढ़ से पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बर्बादी को लेकर कई बार ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार से मांग की गई कि प्रभावितों को 65 हजार 100 रुपये मुआवजा राशि प्रति एकड़ सरकार प्रदान करें। साथ ही फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित खेतों का सर्वे करके राशि जारी की जाए। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है।

एक नजर

विधि के शासन के प्रति निष्ठा ही सभ्य समाज की पहचान है:अशोक



भाटापारा, 27 नवंबर (तछसं.)। संविधान दिवस के अवसर पर गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, में गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अशोक कुमार लाल जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रहे।अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ.निधि मिश्रा ने की सरस्वती वंदना मां सरस्वती एवं भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। मुख्य अतिथि ने भारतीय संविधान की विशेषताओं, उसकी महत्ता, नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने एवं एक जागरूक नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सभी को भारतीय संविधान की शपथ दिलाई तथा संविधान के प्रति निष्ठा, सम्मान एवं उसके आदर्शों का पालन करने का संकल्प दिलाया। अभिनव मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि कृष्ण केशरवानी, संस्कार वाजपेयी, नरेंद्र देवांगन, लोकेश यदु महाविद्यालय के डॉ. महेंद्र कुमार शर्मा, डॉ. किरण चंद्राकर, अफरोज कुरैशी,डॉ. सुरेंद्र साहू उपस्थित रहे। संचालन आमिर हैदर ने कियासमारोह के दौरान महाविद्यालय में आयोजित खेलकूद, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया। अंत में आभार प्रदर्शन एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन हुआ।

दिव्यांगजनों के लिए आयोजित शिविर में 52 लोगों का किया गया पंजीयन

रायगढ़, 27 नवम्बर । समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद पंचायत लैलूंगा में दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) प्रमाणीकरण, चिन्हांकन एवं परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 52 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया। इनमें 16 दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण किया गया, जबकि एक व्यक्ति को मेडिकल रेफर किया गया। इसके अलावा 18 दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड पूर्व में बन चुके थे तथा 17 अन्य श्रेणी में शामिल रहे। शिविर में दिव्यांगजनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया एवं सुविधाओं के संबंध में बताया गया। ज्ञात हो कि आगामी 1 दिसम्बर को पुनः जनपद पंचायत लैलूंगा में दिव्यांग जनों के लिए यूडीआईडी कार्ड प्रमाणीकरण चिन्हांकन परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। जिसमें अधिक से अधिक संख्या में दिव्यांगजन शिविर में शामिल हो सकते है।इसी क्रम में नशामुक्त भारत अभियान के तहत जनपद पंचायत लैलूंगा में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रीति नायडू ने उपस्थित लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने उपस्थित लोगों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई।

ग्रामीण स्वच्छता एवं जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

रायगढ़, 27 नवम्बर । कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री अभिजीत बबन पठारे के मार्गदर्शन में जिला पंचायत रायगढ़ में स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में स्वच्छता समिति के सभापति श्री मुरलीधर राठिया, समिति सदस्य श्री बलदेव कुर्रे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कार्यपालन अभियंता श्रीमती प्रतिभा नवरतन, सहायक अभियंता एवं जिला पंचायत के सहायक परियोजना अधिकारी वीरेन्द्र सिंह राय उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।

नालंदा परिसर, मरीन ड्राइव बैराज, कैनाल लिंक रोड और नवीन सड़क निर्माण सहित

शहर में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 27 नवम्बर। शहर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संचालित विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों को गति देने के लिए कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने आज निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने नालंदा परिसर, मरीन ड्राइव बैराज, कैनाल लिंक रोड तथा गंधरी पुलिया से आरपीएफ पोस्ट तक निर्माणाधीन सड़क का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।



कलेक्टर ने सबसे पहले नालंदा परिसर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को सिविल कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा अन्य आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। लगभग 600 विद्यार्थियों की क्षमता वाली सर्वसुविधायुक्त लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। इसके पूर्ण होने से विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को अध्ययन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मरीन ड्राइव बैराज से नदी में बनी रहेगी जल उपलब्धता

इसके पश्चात कलेक्टर ने मरीन ड्राइव में निर्माणाधीन बैराज का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और इसे निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैराज के निर्माण से नदी में जलस्तर स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी तथा आम नागरिकों को निस्तार के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहेगी।

कलेक्टर ने नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन कैनाल लिंक रोड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चांदनी चौक में निर्माणाधीन अंडरपास का जायजा लिया और कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगर निगम द्वारा अधोसंरचना मद से केवड़ाबाड़ी चौक से मरीन ड्राइव को जोड़ने के लिए इस मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। मार्ग के पूर्ण होने से शहर के मध्य यातायात का दबाव कम होगा तथा सुभाष चौक क्षेत्र में आवागमन सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए मिलेगा वैकल्पिक मार्ग

इसके बाद कलेक्टर ने गंधरी पुलिया से आरपीएफ पोस्ट के पास तक निर्माणाधीन नवीन सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाते हुए इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस सड़क के बन जाने से रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। इससे सुभाष चौक और गांधी प्रतिमा चौक पर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को कहा कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराएं, ताकि शहरवासियों को इन विकास परियोजनाओं का लाभ जल्द मिल सके। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के अधिकारी, संबंधित ठेकेदार एवं सब इंजीनियर उपस्थित थे।

जिले में 592 किसानों ने बेचा 31,802 क्विंटल धान, 244 किसानों को हुआ भुगतान

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 27 नवम्बर । खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी जारी है। 26 नवंबर तक जिले में 592 किसानों से कुल 31,802.40 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में कुल 776.30 लाख रुपये की राशि देय है। अपेक्स बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक 244 किसानों को धान बिक्री का भुगतान किया जा चुका है। शेष किसानों को भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

विकासखंडवार आंकड़ों के अनुसार, धरमजयगढ़ में सबसे अधिक 459 किसानों ने 25,960.80 क्विंटल धान बेचा है। यहां 228 किसानों को भुगतान हुआ है। इसी तरह लैलूंगा में 83 किसानों ने 4,258.40 क्विंटल और पुसौर में 36 किसानों ने 968 क्विंटल धान बेचा है। लैलूंगा में 13 और पुसौर में 3 किसानों को भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा रायगढ़ में 10 किसानों ने 296.40 क्विंटल, तमनार में 2 किसानों ने 186.80 क्विंटल, खरसिया में 1 किसान ने 80 क्विंटल और घरघोड़ा में 1 किसान ने 52 क्विंटल धान बेचा है। उपार्जन केंद्रों में खरीदी प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के साथ किसानों की सुविधा और आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने तथा कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से अवैध धान की खरीदी-बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है।इसके लिए जिले में 20 अंतरराज्यीय चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां तीन पालियों में 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले वाहनों और धान की जांच के लिए राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है तथा जिले की सभी 10 तहसीलों में उड़नदस्ता दल तैनात किए गए हैं। ये दल अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध धान की खरीदी, परिवहन और भंडारण पर नजर रख रहे हैं। अवैध धान के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है।

घरघोड़ा के कारीछापर में अवैध धान भंडारण पर कार्रवाई, 20 क्विंटल धान जब्त



रायगढ़, 27 नवम्बर (तछसं.)। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने और अवैध धान के भंडारण, परिवहन तथा उपार्जन केंद्रों में कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा धान खपाने की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में मंडी विभाग के जांच दल ने घरघोड़ा क्षेत्र के ग्राम कारीछापर में अवैध धान भंडारण का मामला पकड़ा।24 नवंबर को मंडी जांच दल ने ग्राम कारीछापर, घरघोड़ा स्थित जनक निषाद के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान प्रतिष्ठान में 50 बोरियों में कुल 20 क्विंटल धान अवैध रूप से भंडारित पाया गया। मामले में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए धान जब्त किया गया। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में धान के अवैध भंडारण, परिवहन और खरीदी-बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मंडी विभाग द्वारा नियमित रूप से जांच एवं निरीक्षण किया जा रहा है। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

भाटापारा के युवाओं का पुलिस एवं नगर सेना में चयन होने से बढ़ा शहर का मान,शिवरतन शर्मा ने दी बधाई



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भाटापारा, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ पुलिस एवं नगर सेना में चयनित हुए सभी युवाओं से वरिष्ठ भाजपा नेता छत्तीसगढ़ शिवरतन शर्मा ने भेंट कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर चयनित युवाओं को सम्मानित करते हुए शिवरतन शर्मा ने कहा कि आप सभी की मेहनत, अनुशासन और लगन से आज आपने यह सफलता हासिल की है। यही जज्बा आगे भी देश और प्रदेश की सेवा में बनाए रखना। उन्होंने कहा कि भाटापारा विधानसभा के लिए यह बड़े गर्व का विषय है कि यहाँ के युवा आज पुलिस और नगर सेना जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवा देने के लिए चयनित हुए हैं। यह सफलता सिर्फ इन युवाओं की नहीं, बल्कि इनके माता-पिता, गुरुजनों की सफलता है। उन्होंने चयनित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्दी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, सम्मान और सेवा का प्रतीक है। आप सभी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आम जनता की सेवा करें और अपने गांव, परिवार तथा भाटापारा का नाम रोशन करें। शिवरतन शर्मा ने बताया कि भाटापारा विधानसभा के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। शिक्षा, खेल, रोजगार और प्रशिक्षण के क्षेत्र में युवाओं को हर संभव सहयोग दिया जाएगा, ताकि हमारे क्षेत्र का हर युवा आत्मनिर्भर बने और अपने सपनों को साकार कर सके। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। सभी ने चयनित युवाओं को बधाई देकर खुशी व्यक्त की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विकसित ग्राम पंचायत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित

रायगढ़, 27 नवम्बर । जिला पंचायत रायगढ़ के सभाकक्ष में विकसित ग्राम पंचायत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की बेहतर योजना तैयार करने, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन करने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता विकसित करना था।प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदान संस्था के राज्य कार्यालय से प्रशिक्षक आशुतोष नंदा तथा राज्य प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त नोडल अधिकारियों ने मार्गदर्शन दिया। इस दौरान जिला स्तर की समस्त क्रियान्वयन एजेंसियों एवं जनपद स्तर के कार्यक्रम अधिकारियों, सहायक संगणकों और तकनीकी सहायकों को विकसित ग्राम पंचायत योजना की अवधारणा और इसके महत्व से अवगत कराया गया।

आईएसबीएम विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया संविधान दिवस



छुरा, 27 नवंबर । हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' थीम पर आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम, विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का दिया संदेश

ISBM विश्वविद्यालय में संविधान दिवस पूर्ण हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' विषयवस्तु (थीम) के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों एवं उपस्थित जनसमुदाय को भारतीय संविधान के मूल्यों, अधिकारों, कर्तव्यों तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक करना और संविधान के प्रति सम्मान एवं प्रतिबद्धता की भावना विकसित करना था।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जिला पंचायत सदस्य, छुरा श्री लेखराम ध्रुव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉ.आनंद महलवार ने की। इस अवसर पर डीन अकादमिक और आई.क्यू.ए.सी. निदेशक डॉ. एन. के. स्वामी तथा छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. ओ. पी. साहू की गरिमामयी उपस्थिति रही।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री लेखराम ध्रुव ने भारतीय संविधान की आवश्यकता, प्रासंगिकता एवं महत्त्व पर विस्तारपूर्वक अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की आधारशिला होता है। यह प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय का अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ समाज में समरसता और सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से संविधान में निहित आदर्शों एवं मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने तथा एक जागरूक, जिम्मेदार एवं कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने का आह्वान किया।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.आनंद महलवार ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में भारतीय संविधान के निर्माण के ऐतिहासिक घटनाक्रम, उसकी सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा संविधान सभा के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने संविधान की प्रमुख विशेषताओं, विभिन्न अनुच्छेदों एवं समय-समय पर किए गए संवैधानिक संशोधनों की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संविधान देश की विविधता, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान का नियमित अध्ययन करने तथा उसमें वर्णित अधिकारों के साथ-साथ अपने मूल कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहने के लिए प्रेरित किया।इसी क्रम में डॉ. एन. के. स्वामी ने संविधान की महत्ता, उसकी व्यापकता एवं भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि संविधान केवल शासन संचालन का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, समान अवसर, न्याय और समावेशी विकास का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

कोल इंडिया में बेस्ट लार्जेस्ट प्रोडक्शन के लिए एसईसीएल बिलासपुर ने किया सुनील लेंध्रा का सम्मान

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 27 नवंबर। कोल उत्खनन क्षेत्र के कड़े मापदंड,डीजल की किल्लत , तेज बारिश जैसी चुनौतियों के बावजूद रायगढ़ के सुनील अग्रवाल लेंध्रा ने कोल इंडिया का बेस्ट लार्जेस्ट प्रोडक्शन का एवार्ड हासिल किया है। यह सम्मान एस ई सी एल बिलासपुर में सीएमडी हरीश दुहान सहित विभागीय अधिकारियों की गरिमामई मौजूदगी में दिया गया। विदित हो कि एस ई सी एल रायगढ़ के छाल क्षेत्र में सुनील अग्रवाल की कंपनी उत्खनन का कार्य करती है।



सर्वाधिक उत्पादन करने,निर्धारित मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने सहित 126त्न लक्ष्य हासिल करने पर सुनील पूरे कोल इंडिया में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले कांट्रेक्टर बने। एसईसीएल बिलासपुर द्वारा आयोजित गरिमामय समारोह में इस उपलब्धि के लिए सुनील अग्रवाल को बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। बिलासपुर सीएमडी हरीश दुहान की गरिमामयी मौजूदगी में सुनील अग्रवाल, उनके बेटे वैभव अग्रवाल और सरस गोयल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान कोल इंडिया में लार्जेस्ट प्रोडक्शन करने पर प्रदान किया गया। विगत दिनों केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री माननीय जी. किशन रेड्डी का छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ था। इस दौरान उन्होंने कोल उत्खनन और कोल डिस्पैच को लेकर सीएमडी हरीश दुहान की कार्यशैली की सराहना की थी। इस सराहना के बाद यह सम्मान क्षेत्र के लिए विशेष हो गया । यह सम्मान ऐसे समय में मिला है जब देश में कोयला उत्पादन को ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ माना जा रहा है। ऊर्जा की कमी को देखते हुए पीएमओ द्वारा कोल उत्खनन पर विशेष नजर रखी जा रही है। देश भर से कोल उत्पादन से जुड़े आंकड़े प्रतिदिन पीएमओ भेजे जा रहे है। कोल उत्खनन का काम चुनौतियों से भरा होता है । लेकिन सीएमडी बिलासपुर के नेतृत्व एवं जीएम रायगढ़ के कुशल मार्गदर्शन में सुनील अग्रवाल के कुशल प्रबंधन ने इन सभी बाधाओं को पार किया। क्षमता से अधिक कार्य करते हुए उन्होंने जो लक्ष्य हासिल किया, वह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि टीम वर्क, अनुशासन और हिम्मत की मिसाल है। उत्खनन के लिए बेहद कड़े मापदंड निर्धारित है इसलिए यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है। सुनील अग्रवाल की टीम ने इन सभी कड़े मापदंडों का पालन करते हुए उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया, यही वजह है कि यह सम्मान सिर्फ उत्पादन का नहीं, बल्कि अनुशासित और सुरक्षित खनन का भी सम्मान है। इस अवसर पर सुनील अग्रवाल ने सीएमडी हरीश दुहान का विशेष आभार जताते हुए कहा कि उनके कुशल मार्गदर्शन में ही लक्ष्य हासिल हो सका। इस उपलब्धि के लिए सभी लोगों के टीम वर्क को भी श्रेय दिया। एसईसीएल रायगढ़ जीएम मनोज कुमार,सब एरिया मैनेजर छाल सुरेंद्र नाथ,कॉलरी मैनेजर सोमरा जी,सहित समस्त सहयोगियों का भी सुनील ने विशेष आभार जताते हुए कहा एसईसीएल के सहयोगात्मक भावना सराहनीय है। बड़ा लक्ष्य सभी के सहयोग से ही पूरा हो सकता है। विदित हो कि रायगढ़ की सामाजिक गतिविधियों में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले सुनील अग्रवाल को पहले भी बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर के अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है । प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सुनील अग्रवाल नई पीढ़ी के ठेकेदारों के लिए प्रेरणा भी हैं।यह सम्मान बताता है समय के पहले भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है । छत्तीसगढ़ में सुनील लैंध्रा निर्धारित समय में तेज गति के साथ-साथ गुणवत्तापूर्वक कार्य के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी यह सफलता युवा ठेकेदारों को यह संदेश देती है कि चुनौतियों का डटकर सामना करना ही सफलता की कुंजी है। सुनील अग्रवाल ने यह साबित किया है कि मजबूत इरादे के साथ मजबूत टीम को सही मार्गदर्शन मिले तो कठिन परिस्थितियां भी लक्ष्य को रोक नहीं सकतीं।सीएमडी हरीश दुहान के कुशल नेतृत्व का परिणाम – बिलासपुर को मिला लार्जेस्ट प्रोडक्शन का सम्मानवर्ष 2025 में कार्यभार संभालने के बाद एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहान के कुशल मार्गदर्शन एवं बेहतर प्रबंधन की वजह से कोयला उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उत्पादन से लेकर डिस्पैच तक हर स्तर पर अनुशासन, पारदर्शिता और टीम वर्क को प्राथमिकता दी गई। इसी का परिणाम है कि कोल इंडिया में प्रोडक्शन का पुरस्कार बिलासपुर क्षेत्र को मिला। यह सम्मान सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि कुशल नेतृत्व और सामूहिक मेहनत का प्रमाण है।

समाचार संक्षेप

संविधान दिवस पर कचना धुरुवा महाविद्यालय छुरा में 'विकसित भारत युवा संवाद' आयोजित



छुरा, 27 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। मेरा युवा भारत (MY Bharat) गरियाबंद, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में संविधान दिवस के अवसर पर आज कचना धुरुवा महाविद्यालय, छुरा में 'विकसित भारत युवा संवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक नरेन्द्र साहू एवं फलेश मंडावी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत रहा।कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ना, नशे एवं मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा युवाओं को नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना था।कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं अतिथि के रूप में समाजसेवी श्री शीतल ध्रुव सहित हेमशिखर ध्रुव (शहीद पंकज विक्रम सम्मान से अलंकृत), पोखन ठाकुर एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों के साथ अपने जीवन के अनुभव, संघर्ष, सामाजिक कार्यों एवं उपलब्धियों को साझा करते हुए युवाओं को सकारात्मक सोच, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।इस अवसर पर श्री शीतल ध्रुव ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश के विकास में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नशे की लत से होने वाले शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का युवा स्वस्थ, शिक्षित, जागरूक और नशे से मुक्त होगा।हेमशिखर ध्रुव सहित अन्य अतिथियों ने भी विद्यार्थियों को अपने प्रेरणादायक जीवन प्रसंगों के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों का बोध कराया। उन्होंने युवाओं से अपने जीवन में सकारात्मक आदतें अपनाने और समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों एवं उपस्थित अतिथियों ने संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के मूल्यों को आत्मसात करने तथा एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया।

कचना धुरवा कॉलेज के एनएसएस शिविर में नशा व टीबीमुक्त गांव का संदेश दिया गया



छुरा, 27 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित तथा शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़) के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सात दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह सात दिवसीय शिविर 21 नवंबर 2026 से 27 नवंबर 2026 तक ग्राम कनेसर, तहसील छुरा, जिला गरियाबंद (छ.ग.) में ÷नशा एवं टीबी-मुक्त युवा÷ विषय पर संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत आयोजित योगाभ्यास सत्र में शिविरार्थियों को प्रतिदिन योग और प्राणायाम करने के लाभों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर योगाचार्य मिथलेश कुमार सिन्हा और योगाचार्य गणेश आजाद ने शिविरार्थियों को योगाभ्यास कराया। शिविरार्थियों ने विभिन्न योगासनों और प्राणायाम का उत्साहपूर्वक अभ्यास किया। आयोजकों के अनुसार, इस प्रकार के आयोजनों से स्वयंसेवकों में सेवा भावना, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति प्रतिबद्धता और अधिक सुदृढ़ होती है। वक्ताओं और प्रशिक्षकों ने बताया कि नियमित योगाभ्यास न केवल तन और मन को स्वस्थ व ऊर्जावान रखता है, बल्कि युवाओं को अनुशासित और सकारात्मक दिशा भी प्रदान करता है।

आदिवासी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास छुरा में मनाया गया संविधान दिवस



छुरा, 27 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। नगर के आदिवासी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में संविधान दिवस श्रद्धा,सम्मान एवं उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम भारतरत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर पूजा-अर्चना एवं माल्यार्पण कर किया गया।इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने भारतीय संविधान के महत्व, संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को जागरूक किया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीलकंठ सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज गरियाबंद जिलाध्यक्ष जिला संरक्षक छतरसिंह ठाकुर, जिला सचिव शीतल ध्रुव, जनपद सदस्य सुखबती टाण्डे, छात्रावास अधीक्षक कुलेश्वर मरकाम, नागवंशी दीवान, कन्हैया लाल यदु, जिला मीडिया प्रभारी पुनितराम ठाकुर उपस्थित रहे।इस अवसर पर छात्र-छात्राओं द्वारा सभी अतिथियों का पीला चावल लेकर स्वागत किया गया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीलकंठ सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं सम्मान का अधिकार प्रदान करता है।

एक नजर

संवेदनाओं से सुशासन की नई इबारत लिख रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर, 27 नवंबर। नेतृत्व की सार्थकता इस बात में निहित है कि सामान्य जन की पीड़ा को महसूस करना, किसी बुजुर्ग की आंखों में छिपी विवशता को समझना, एक मां की चिंता को अपनी चिंता मानना और संघर्ष कर रही किसी बेटी के सपनों को टूटने से बचाने के लिए आगे आना यही मानवीय मूल्यों को संरक्षित करना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली में मानवीय संवेदनाओं का यही सुंदर स्वरूप दिखाई देता है। उनके लिए जनसेवा महज एक प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों से जुड़ा एक संकल्प है। उनकी सहजता, सरलता और आत्मीयता शासन को आम नागरिकों के और करीब ला रही है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की सफलता का आकलन केवल विकास के आंकड़ों, अधोसंरचनाओं के निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन से नहीं किया जा सकता। उसकी वास्तविक कसौटी यह है कि समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की कार्यशैली में इसी विचार की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। उनके नेतृत्व में विकास और मानवीय संवेदनाएं एक दूसरे की पूरक बन रही हैं। शासन की प्राथमिकताओं में जहां प्रदेश की प्रगति है, वहीं उस प्रगति के केंद्र में आम नागरिक का सुख, सम्मान और बेहतर भविष्य भी है। मुख्यमंत्री श्री साय के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहजता है। पद की गरिमा के साथ व्यवहार की सरलता बनाए रखना उनके नेतृत्व को विशिष्ट बनाता है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन में जब प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से आए नागरिक उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखते हैं, तब उनके व्यवहार में एक अभिभावक जैसी आत्मीयता दिखाई देती है। किसी की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, उसकी परिस्थितियों को समझना और समाधान के लिए तत्काल पहल करना संवेदनशील नेतृत्व की पहचान है।

चार नर्सिंग पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 27 नवंबर से आवेदन

रायपुर, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ में प्रवेश वर्ष 2026 के लिए चार नर्सिंग पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु स्ट्रे राउंड की काउंसिलिंग के लिए नए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य काउंसिलिंग समिति, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ के अनुसार अभ्यर्थी 27 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे से 28 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे तक संचालनालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। इस चरण में भाग लेने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदनों की जाँच (स्क्रूटनी) और प्रवेश की प्रक्रिया 29 से 30 नवंबर 2026 तक पूरी की जाएगी। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए द्वितीय एवं तृतीय (मॉपअप) संयुक्त चरण की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 25 से 26 नवंबर 2026 तक संपन्न हुई। इस संयुक्त चरण में प्रवेश के बाद रिक्त रह गई सीटों के लिए स्ट्रे राउंड की काउंसिलिंग आयोजित की जा रही है। समिति ने बताया कि संयुक्त चरण के बाद शेष रिक्त सीटों के संवर्ग, श्रेणी एवं नियतांश में परिवर्तन छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2026 के नियम 10 और 11 के अनुसार किया गया है। इसके तहत सभी रिक्त आरक्षित सीटों को 'अनारक्षित बिना संवर्ग' में परिवर्तित किया गया है। नए ऑनलाइन आवेदन के लिए उक्त पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटें 'अनारक्षित बिना संवर्ग' की हैं, जबकि शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों की सभी रिक्त सीटें 'अनारक्षित महिला संवर्ग' की हैं। राज्य शासन की अनुमति के बाद बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 10 परसेंटाइल तक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जायेंगे। यह प्रावधान केवल बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए लागू है।

सुशासन और जनकल्याण के संकल्प से छत्तीसगढ़ में विकास का नया अध्याय : मुख्यमंत्री

रायपुर, 27 नवंबर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सुशासन, जनकल्याण और समृद्धि के नए संकल्पों के साथ विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने बीते तीन वर्षों में किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और जनजातीय समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों से जहां प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग और अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में नई संभावनाओं का विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हुए प्रदेश के तीन करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाना है।



मुख्यमंत्री श्री साय आज आईएनडी-24 न्यूज चैनल के विशेष कार्यक्रम 'मुख्यमंत्री जी से संवाद ङ्क छत्तीसगढ़ के विकास का विजन' में प्रदेश के विकास और भविष्य की कार्ययोजना पर अपने विचार साझा कर रहे थे। उन्होंने सरकार की तीन वर्षों की उपलब्धियों, प्रधानमंत्री की गारंटियों के क्रियान्वयन, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तीकरण, कृषि विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा बस्तर में शांति और विकास के नए दौर सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दिसंबर 2023 में सरकार गठन के साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने का कार्य प्रारंभ किया गया। पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। किसानों को दो वर्षों का लंबित धान बोनस प्रदान किया गया और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की व्यवस्था लागू की गई। तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उनका लाभ पात्र हितग्राहियों तक सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर जैसे दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। गीदम में मेडिकल कॉलेज और जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का संचालन प्रारंभ हुआ है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से सुदूर गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब खनिज आधारित पारंपरिक उद्योगों के साथ आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और रोजगार आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले तीन वर्षों में प्रदेश को 8.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लगभग 50 प्रतिशत निवेश परियोजनाएं आधुनिक तकनीक और अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में निवेश और कारोबार को सुगम बनाने के लिए 450 से अधिक सुधार किए गए हैं। दो जनविश्वास अधिनियमों के माध्यम से दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

कर्मचारियों की कमी से चरमराती प्रशासनिक व्यवस्था, आखिर कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा शासन की योजनाओं का लाभ

■ उत्तम साहू

नगरी 27 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। धमतरी जिले सहित प्रदेश में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर सरकार लगातार बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन इन योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले शासकीय विभाग ही कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। प्रदेश के अनेक सरकारी कार्यालयों में नियमित अधिकारी-कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। कहीं एक कर्मचारी के भरोसे कई शाखाओं का काम चल रहा है, तो कहीं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के सहारे विभागीय जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी दफ्तरों में पर्याप्त कर्मचारी ही नहीं होंगे, तो शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता और अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा?

सरकार की योजनाएं केवल घोषणाओं और सरकारी आदेशों से सफल नहीं होतीं। उनके क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित अधिकारी-कर्मचारियों की जरूरत होती है। पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, कृषि, आदिवासी विकास और अन्य विभागों में कर्मचारियों की उपलब्धता प्रशासनिक कामकाज की बुनियादी आवश्यकता है। लेकिन जब विभागों में पद खाली पड़े हों और उपलब्ध कर्मचारियों पर लगातार अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ हो, तो



कामकाज प्रभावित होना स्वाभाविक है।

दैनिक वेतनभोगियों के भरोसे कब तक चलेगा सरकारी कामकाज: स्थिति का एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि कई कार्यालयों में नियमित कर्मचारियों की कमी के बीच दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। ये कर्मचारी भी विभागीय कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन स्थायी और पर्याप्त मानव संसाधन के अभाव में प्रशासनिक व्यवस्था को लंबे समय तक इसी तरह चलाना कितना उचित है? दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के भरोसे महत्वपूर्ण विभागीय जिम्मेदारियां निभाना न तो स्थायी समाधान है और न ही इससे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है।

वहीं नियमित कर्मचारियों की कमी के कारण मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ता है। इसका असर फाइलों के निराकरण, आम नागरिकों की शिकायतों, प्रमाण पत्रों, राजस्व प्रकरणों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव और अधिक दिखाई देता है, जहां लोगों को छोटे-छोटे शासकीय कार्यों के लिए भी बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

भर्ती के बिना सुचारू प्रशासन की उम्मीद कैसे: सरकार यदि वास्तव में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती है, तो उसे सबसे पहले सरकारी विभागों में रिक्त पदों की स्थिति की समीक्षा करनी होगी। विभागवार स्वीकृत पद, कार्यरत कर्मचारी और रिक्त पदों का वास्तविक आंकड़ा सार्वजनिक कर भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार नियमित भर्ती के साथ तकनीकी और मैदानी अमले की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी।

एक ओर प्रदेश के शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाना युवाओं को रोजगार देने के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

सरकार की जवाबदेही पर बड़ा सवाल : आखिर सरकार प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कितनी गंभीर है? क्या सरकारी कार्यालयों को पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता में शामिल है या फिर सीमित कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगियों के सहारे ही व्यवस्था चलाने की कोशिश की जा रही है? यदि समय रहते रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हुई, तो योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और आम जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने की चुनौती और बढ़ सकती है।

सरकार को यह समझना होगा कि मजबूत प्रशासन के बिना सुशासन का दावा अधूरा है। केवल योजनाएं बनाना और बजट स्वीकृत करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार और पर्याप्त अधिकारी-कर्मचारी भी जरूरी हैं। जनता को घोषणाएं नहीं, सुचारू प्रशासन चाहिए।

युवाओं को रोजगार चाहिए और सरकारी कार्यालयों को पर्याप्त कर्मचारी। अब सवाल सरकार से है कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती कब होगी? आखिर कब तक सरकारी दफ्तरों का कामकाज कर्मचारियों की कमी और सीमित संसाधनों के भरोसे चलता रहेगा? क्या सरकार प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहती है या फिर इसे भगवान भरोसे छोड़ने की स्थिति बनी रहेगी?

ग्रामीण विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करें: दिव्या अग्रवाल



■ जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला मे तकनीकी दक्षता एवं मैदानी क्रियान्वयन पर दिया जोर

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार, 27 नवंबर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष मे वीबी -जी राम जी अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी दक्षता, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा समयबद्ध प्रगति के संबंध में मार्गदर्शन एवं आवश्यक निर्देश दिए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्रामीण विकास में मैदानी अमले की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारी का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों को बेहतर बनाने में किया जाए। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों की योजना तैयार करने, ग्रामीण परिवारों को मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने तथा उपयोगी एवं टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उन्होंने वींज़ीपीपी पोर्टल पर व्यवस्थित कार्ययोजना तैयार करने एवं परिसंपत्तियों की सही मार्किंग,तकनीकी प्राक्कलन तथा मापन संबंधी प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अभिलेखों, पोर्टल पर दर्ज जानकारी और वास्तविक मैदानी स्थिति में एकरूपता रखने तथा प्रगति की नियमित समीक्षा पर जोर दिया।जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने 'मोर गांवङ्कमोर पानी' महाअभियान के अंतर्गत स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समन्वित प्रयास करने का मार्गदर्शन दिया। जलदूत ऐप में शतप्रतिशत एवं सही प्रविष्टियां सुनिश्चित करने तथा युक्तधारा और अनुमेय कार्यों की जानकारी का उपयोग ग्राम पंचायतों की आवश्यकता आधारित योजना बनाने में करने पर बल दिया गया।

कार्यशाला में मेटों के कार्यस्थल पर तकनीकी प्रशिक्षण, अभियंताओं एवं संबंधित विभागों के समन्वय, ई -सक्षम हिंदी पाठ्यक्रम एवं प्रमाणन, संतृप्तता आधारित विशिष्ट कार्यों तथा शतप्रतिशत मूल्यांकन एवं सत्यापन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदया ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर नियमित मैदानी निरीक्षण, गुणवत्ता की निगरानी और लंबित कार्यों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।

जिला कार्यालय में संविधान दिवस संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन कर मनाया गया

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार, 27 नवंबर। जिले मे 26 नवम्बर को संबिधान दिवस मनाया गया। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में महात्मा गांधी, संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर, छत्तीसगढ़ महतारी एवं शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके पश्चात संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया गया तथा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली गई।

कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के कारण ही



हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के साथ जीवन जी रहे हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संविधान के दायरे में रहकर अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने का आह्वान किया।

ज्ञातव्य है कि प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर वर्ष 2015 में भारत सरकार ने पहली बार देशभर में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। तब से प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अवध राम टंडन, निशा नेताम मड़ावी,सीमा ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी -कर्मचारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री साव संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का करेंगे शुभारंभ

रायपुर, 27 नवंबर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव 27 नवम्बर को अम्बिकापुर में संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ करेंगे। वे शुक्रवार को सरगुजा, बिलासपुर और मुंगेली जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बिलासपुर में प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन और गौरव सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री शाम को मुंगेली व्यापार मेला-2026 का भी शुभारंभ करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार 27 नवम्बर को सवेरे 10 बजे बिलासपुर से शासकीय विमान से अम्बिकापुर के लिए रवाना होंगे। वे सवेरे 11 बजे अम्बिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ करेंगे।

वीरभूमि सोनाखान में 10 दिसंबर को होगा शहादत दिवस का गरिमामय आयोजन



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 दिसंबर को वीरभूमि सोनाखान में शहादत दिवस का गरिमामय आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर गुरुवार को कलेक्टर कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में आयोजन समिति के सदस्यों एवं अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई।बैठक में शहादत दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि इस वर्ष भी सोनाखान में शहीद वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आगमन प्रस्तावित है। उन्होंने आयोजन को भव्य एवं गरिमामय बनाने तथा आमजन के लिए आवश्यक सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने सड़कों के पैच रिपेयर, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, सामाजिकजनों के लिए विश्राम एवं भोजन व्यवस्था, मंच निर्माण सहित अन्य आवश्यक तैयारियों के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने कहा।

आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि 8 एवं 9 दिसंबर को मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। शहादत दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।

छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार के नए द्वार

रायपुर, 27 नवंबर। धान के कटोरे के रूप में विख्यात छत्तीसगढ़ की कृषि संपदा अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश के पारंपरिक सुगंधित चावल एवं अन्य विशिष्ट कृषि उत्पादों को वैश्विक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए स्पेन के बार्सिलोना में महत्वपूर्ण पहल की गई है। छत्तीसगढ़ के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के नेतृत में स्पेन पहुंचे राज्य के प्रतिनिधिमंडल की फिरा बार्सिलोना संस्था के सीईओ श्री रिकॉर्ड जेप्टरो के साथ बैठक हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी एवं संचालक कृषि श्री राहुल देव शामिल थे। बैठक में छत्तीसगढ़ के विशिष्ट कृषि उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता, निर्यात की संभावनाओं तथा यूरोपीय बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जेप्टरों ने छत्तीसगढ़ शासन के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश के जवाफूल, जीराफूल, नगरी दुबराज और कालीमूंछ सहित अन्य विशिष्ट कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रचारित करने में सहयोग की बात कही गौरतलब है कि उक्त संस्था भारत सहित विभिन्न देशों व राज्यों के साथ व्यावसायिक समन्वय स्थापित कर कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंचों तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करती है। देश के मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में समन्वय के बाद इस पहल से छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि उद्यमियों एवं निर्यातकों को विदेशी खरीदारों से जुड़ने के नए अवसर मिलने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ के पारंपरिक सुगंधित चावल अपनी विशिष्ट खुशबू, स्वाद और गुणवत्ता के कारण अलग पहचान रखते हैं। प्रदेश के जीराफूल और नगरी दुबराज चावल को भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग) भी प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रभावी ब्रांडिंग से किसानों को उनकी विशिष्ट उपज का बेहतर मूल्य मिलने के साथ ही पारंपरिक धान की किस्मों के संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।

भगवान के मंदिर में भी चोरी करने के लिए लोग तैयार हैं : श्री अक्षय मुनि जी मसा

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बालोद / मालीघोरी 27 नवंबर। शासन दीपक श्री अक्षय मुनि जी मसा ने जैन भवन मालीघोरी की धर्म सभा में फरमाया कि संसार में आदमी कला सीखता है ,अनुभव सीख रहा है, कला 72 प्रकार की बताई गई है। आदमी चीजें बनाने में परफेक्ट है कला एक अलग बात है जिंदगी जीना अलग है। आज सिर्फ अनुभव हासिल करते रह जाते हैं, याद रखिए अनुभवी व्यक्ति चालाकी भी ज्यादा करता है। मन बहुत कुछ करा लेता है हमारे से , संसार की रचना भी , मन ही करता है। मन परिकल्पनाओं का है संसार। मन धरातल में होगा तब हम आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। आज की जिंदगी हमारी दूसरे के हाथ में है स्वयं के हाथ में नहीं । जब खुद के हाथ में हमारी जिंदगी नहीं तो किस काम की है । सापेक्षता में जीते हैं ,मन सापेक्षता में ही रहता है , आत्मा



निरपेक्ष है। हम मित्र कब बनाते हैं ? जब दुश्मन मौजूद है तो मित्र बनाना ही पड़ता है , जैसे गर्मी लगती है तो हम एसी लगा लेते हैं। आज तो देखते हैं कि भगवान के मंदिर में भी लोग चोरी कर लेते हैं , व्यक्ति को कहीं जाने का नहीं जहां पर है वही मंदिर ही बना लो।

जैन मुनि ने आगे कहा कि जीवन को साधने का मौका मिला है जीवन मतलब सांसों का पता होना चाहिए, गफ्लत की नींद में मत सोएं। श्वांसों में राम प्रकट होगा तो कस्तूरी भी भीतर से नजर आएगी, विवेक रखेंगे तो मौन प्रकट हो जाएगा। भोजन शांति से करना भोजन करते समय एक रोटी कुत्ता गाय, व बिल्ली को दूध पिलाना , जीव प्राणी के लिए भोजन निकालना । प्रेम से खिलाएंगे तो प्रेम हृदय में प्रकट होगा। आज व्यक्ति का पत्थर जैसा दिल हो गया है, फूलों की तरह खिलना स्वयं को ही पड़ेगा। स्वयं की चेतना स्वयं को ही जलाना होगा। चोरी नहीं करेंगे तो दान देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्ति तृष्णा में डूबा हुआ है। संत को प्राईज या टाइटल की जरूरत नहीं है, संत अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। याद रखें सोसाइटी समाज हमेशा दोनों और बोलती है, हर व्यक्ति द्विमुखी है ,चेतना में चला जाता है इंसान। चेतना के धरातल को समझो, स्वयं अपने में जीरो, समस्या हम ही खड़ी करते हैं और उससे हमें जूझ रहे हैं। संसार की यह विचित्र हालत है , जीवन को तारने वाला कोई नहीं। जिंदगी को कैसे जीना यदि हम धरती विश्व को परिवार बना लिया । फूलों की तरह रहना है तो कांटों के साथ जीना सीख ले । समाज में रहकर ही बांसुरी बजाना है । मच्छर को मत मारो तुम्हारी भी कब्र एक दिन खुद जाएगी , सृष्टि में तुम्हारी भी कब्र खुद जाएगी । दिल में हिंसा मौजूद है तब तक प्रेम की बांसुरी नहीं बजेगी चाहे कितना ही तीर्थ यात्राएं कर लें। हिंसा के प्रति हमेशा जागृत रहे याद रखें दुश्मन में हीं दोस्त छिपा है। संसार में कब कौन पलटा खाएगा पता ही नहीं पड़ पाएगा । नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति ताना मारते हैं , पीड़ा की पता नहीं कर पाते याद रखें यह एक दिन पुनः लौटकर आएगा संसार इको साउंड की तरह है, धरती को नरक बनाने में लगे हुए हैं स्वर्ग ही नहीं बन पा रहे हैं डीजे, प्रदूषण, पटाखे फोड़कर । दूसरे की पीड़ा को समझो। संसार की विचित्रता को देखकर प्रभावित नहीं होना दया मय, करुणा मत बनना। प्रवचन सभा में आज ग्रामवासी मौजूद थे। विकास नाहटा सुपुत्र हमीरमल नाहटा बालोद के आज 30 उपवास तपस्या है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 2982/न.पा./रा.वि./2026-27
तिल्दा-नेवरा, दिनांक 26/11/2026

ईश्तहार-सूचना

एतद् द्वारा आम सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री जय प्रकाश साहू पिता स्व. श्री बहुर सिंग वार्ड क्रं. 04 गुरु घासीदास वार्ड तिल्दा-नेवरा जिला रायपुर निवासी द्वारा नगर पालिका क्षेत्र श्री अवसंत दास साहू पिता स्व. श्री बहुर सिंग वार्ड क्रं. 04 गुरु घासीदास वार्ड तिल्दा-नेवरा जिला रायपुर में भूमि/भवन का रजिस्ट्री पेपर एवं निम्न दस्तावेज संलग्न कर निकाय तिल्दा-नेवरा में हकहस्तांतरण हेतु आवेदन पेश किया गया है।

उक्त शपथ पत्र के आधार पर भवन/भूमि वार्ड क्र. 04 में स्थित हैं नगर पालिका डिमांड पंजी में नाम दर्ज नहीं है। नगर पालिका के कर अभिलेख में दर्ज किये जाने की मांग किया गया है। उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति हो तो वह ईश्तहार/विज्ञापन प्रकाशन से 30 दिवस के अन्दर में दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत अवधि बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 26/11/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मोहर लगाकर जारी किया जाता है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद
तिल्दा-नेवरा

मुहर

एक नजर

नेस्ले इंडिया का सफाई अभियान

रायपुर, 27 नवम्बर। पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक भलाई के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के तहत, नेस्ले इंडिया ने आज क्लीन कॉरिडोर गुरुग्राम की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य गुरुग्राम में एम्बिएंस मॉल और राजीव चौक के बीच नेशनल हाईवे के 16 किलोमीटर लंबे हिस्से में स्वच्छता और रखरखाव को बेहतर बनाना है। यह हिस्सा दिल्ली और गुरुग्राम के बीच काम के सिलसिले में रोज़ाना आने-जाने वाले हज़ारों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न समुदायों और कार्यस्थलों को जोड़ता है। दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, खासकर सर्दियों के आने वाले महीनों में, ऐसे में सार्वजनिक स्थानों को साफरखने के लिए लगातार प्रयासों की ज़रूरत और भी बढ़ गई है। इस पहल के तहत, कॉरिडोर पर धूल और ठोस कचरे की समस्या से निपटने के लिए मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव और आठ कर्मचारियों द्वारा रोज़ाना कचरा इकट्ठा करने का काम किया जाएगा। इसमें इफ्को चौक को सुंदर बनाने के लिए वहां हैंगिंग प्लांटर्स (लटकने वाले पौधे) लगाना और नियमित रूप से सफाई अभियान चलाना भी शामिल है।

तिवारी ने की सिद्धार्थ शंभू से मुलाकात



रायपुर, 27 नवम्बर। भाजपा किसान नेता एवं सर्व हिंदू सनातन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश तिवारी ने राष्ट्रीय मंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश सह-प्रभारी सिद्धार्थ शंभू से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर योगेश तिवारी ने सिद्धार्थ शंभू को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनका आत्मीय अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच आत्मीय संवाद हुआ। योगेश तिवारी ने सिद्धार्थ शंभू के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए बेमेतरा जिले के संगठनात्मक और राजनीतिक गतिविधियों, के बारे में जानकारी दी और सामाजिक सहभागिता और जनसेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

कन्नौजिया साहू समाज ने किया कंबल वितरण



रायपुर, 27 नवम्बर। कन्नौजिया साहू समाज जन कल्याण समिति ने शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उ.मा. विद्यालय मठपुरैना रायपुर में कंबल वितरण किया। यह कार्यक्रम अभिमन्यु साहू के सौजन्य से उनकी माता शकुंतला साहू द्वारा संपन्न किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद साहू, संरक्षक सदस्य उमाशंकर ने की।

कांग्रेस की बैठक से गायब तीन जिलाध्यक्षों को नोटिस



रायपुर, 27 नवम्बर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने संगठन को सक्रिय करने की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने गुरुवार को राजीव भवन में जिला अध्यक्षों, नगरीय निकाय चुनाव प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की अहम बैठक ली। एक घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में चुनावी रणनीति, संगठनात्मक समन्वय और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले तीन जिला अध्यक्षों पर प्रदेश प्रभारी ने नाराजगी जताई और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

15 दिसंबर तक बूथ स्तर पर चलेगा वोट रक्षक अभियानस्थानीय मुद्दों और प्रत्याशियों की सक्रियता पर होगा फोकसभाजपा पर साधा निशाना, लोकतांत्रिक परंपराओं पर उठाए सवालबैठक से गायब रहे तीन जिलाध्यक्ष, जारी होगा कारण बताओ नोटिस

15 दिसंबर तक बूथ स्तर पर चलेगा वोट रक्षक अभियान: बैठक में वोट चोरी के खिलाफ चल रहे वोट रक्षक अभियान को 15 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला लिया गया। कांग्रेस इस अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने की तैयारी में है। इसके बाद किसानों और बिजली से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी।

बैठक में पटवारी हड़ताल, किसानों की समस्याओं और बिजली व्यवस्था समेत आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने पर जोर दिया गया।

उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होते हैं। इनमें स्थानीय मुद्दे और बुनियादी सुविधाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्याशियों के चयन में उनकी सक्रियता और जनता के बीच स्वीकार्यता को ध्यान में रखा जाएगा। फिलहाल चुनावी एजेंडा तय नहीं हुआ है।

स्थानीय मुद्दों और प्रत्याशियों की सक्रियता पर होगा फोकस

बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने कहा कि संविधान रक्षा मार्च के तहत जिला अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक स्थिति और उनकी समस्याओं पर चर्चा की गई है। वोट चोरी के खिलाफचल रहे अभियान की समीक्षा भी की गई। नगरीय निकाय चुनाव के पर्यवेक्षकों के साथ बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया गया है।

भाजपा पर साधा निशाना, लोकतांत्रिक परंपराओं पर उठाए सवाल

सुखदेव भगत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसकी नीयत साफनहीं है और उसे लोकतांत्रिक पद्धति एवं परंपराओं पर विश्वास नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हालात में लोगों का झुकाव कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे आंदोलन करेगी।

अनुशासन और जवाबदेही मजबूत करने की कवायद

कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण बैठक में तीन जिला अध्यक्षों की अनुपस्थिति ने संगठन के भीतर सख्ती का संकेत दिया है। बताया गया कि कांकेर के रवि घोष, अंबिकापुर के बालकृष्ण पाठक और रायगढ़ ग्रामीण के नेगी बिना पूर्व सूचना दिए बैठक में शामिल नहीं हुए। इस पर प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने नाराजगी जताई और तीनों जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। संगठन की इस कार्रवाई को चुनाव से पहले अनुशासन और जवाबदेही मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

निजी परिवहन श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन की मांग



रायपुर, 27 नवम्बर। छत्तीसगढ़ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ ने राज्य के निजी परिवहन श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं, उनके अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की है। बैठक में भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी गीता सोनी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेश स्वामी, रायपुर भारतीय मजदूर संघ रायपुर जिला मंत्री मिथुन मानिकपुरी अध्यक्ष पवन उगले कार्यकारी अध्यक्ष परमेश्वर कनौजिया सह मंत्री रानी सोनी एवं कार्यसमिति सदस्य प्रशांत सोनी, ममता रायपुर रेलवे स्टेशन प्रीपेड ऑटो चालक संघ के महामंत्री दीपक मुड़ियार अन्य पदाधिकारी, भाटापारा परिवहन चालक-परिचालक संघ से गोविंद, विनोद, शिव साहू, ड्राइवर एकता मजदूर संघ शक्ति एवं रायगढ़ जिला प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर संघ से सुलेश्वर पटेल, संतोष चौहान, गणेश पटेल, सूरजपुर ट्रांसपोर्ट मजदूर संघ की संगटन मंत्री विनोद ठाकुर और अन्य प्रतिनिधि ने भाग लिया।

छत्तीसगढ़ में अब तक कल्याण बोर्ड का गठन नहीं: इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी गीता सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक निजी परिवहन श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। इस संबंध में पिछले अक्टूबर माह में छत्तीसगढ़ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की गई थी।

उन्होंने कहा कि ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा, कैब, ट्रक एवं अन्य निजी परिवहन साधनों से जुड़े लाखों श्रमिक दिन-रात मेहनत करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, दुर्घटना बीमा एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

राष्ट्रीय स्टील एवं पावर एक्सपो 30 नवंबर तक



रायपुर, 27 नवम्बर। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक राजधानी के रूप में पहचाने जाने वाले रायपुर में देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक आयोजनों में से एक 16वें राष्ट्रीय एक्सपो (स्टील एवं पावर) का आयोजन होने जा रहा है। यह चार दिवसीय औद्योगिक प्रदर्शनी 27 से 30 नवम्बर 2026 तक साइंस कॉलेज ग्राउंड, रायपुर में आयोजित की जाएगी। यह आयोजन उद्योग जगत को नई तकनीकों, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नवाचारों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा।

इंदौर इन्फोलाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित यह नेशनल एक्सपो रायपुर में स्टील, पावर, सीमेंट, माइनिंग, हेवी इंजीनियरिंग और संबद्ध क्षेत्रों की प्रमुख औद्योगिक प्रदर्शनियों में से एक है। अपने पिछले 15 संस्करणों में यह आयोजन 4, 000 से अधिक प्रदर्शकों और 90, 000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों को आकर्षित कर चुका है, जिससे यह मध्य भारत का एक प्रभावशाली औद्योगिक आयोजन बन गया है। इस एक्सपो को उरला इंडस्ट्रीज् एसोसिएशन, रायपुर का विशेष सहयोग प्राप्त है। यह प्रदर्शनी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मिनिस्ट्री) द्वारा अनुमोदित है तथा पीएमएस योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले एमएसएमई उद्यमों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। यह पहल स्टार्टअप्स तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अपने उत्पादों और सेवाओं के प्रचार-प्रसार का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है।

बच्चों की खरीद-फरोख्त पर रायपुर कलेक्टर का एक्शन

दिवाकर अस्पताल लाइसेंस निरस्त करने नोटिस जारी, सात आरोपी गिरफ्तार

रायपुर, 27 नवम्बर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवजात शिशुओं की खरीद-फरोख्त के गंभीर मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने गोगांव स्थित दिवाकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को 30 दिन का नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इस मामले में पुलिस अब तक एक डॉक्टर समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं, जांच में इस अवैध नेटवर्क के आठ राज्यों तक फैले होने की बात सामने आई है।

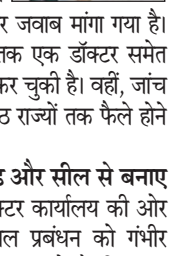

अस्पताल के लेटरहेड और सील से बनाए गए फर्जी दस्तावेज: कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में अस्पताल प्रबंधन को गंभीर अनियमितताओं पर अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अस्पताल में प्रसव नहीं होने के बावजूद नवजात शिशुओं के फर्जी डिस्चार्ज टिकट और मेमो तैयार किए गए। इसके लिए अस्पताल के लेटरहेड, सील और हस्ताक्षर का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया। आरोप है कि बच्चों को खरीदने वाले दंपतियों के आधार कार्ड लेकर इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नगर निगम में आवेदन किए गए और कथित तौर पर अवैध तरीके से जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाए गए। प्रशासन ने इसे गंभीर मामला मानते हुए नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। आरोपियों ने महिला की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुए नवजात बच्चे को निःसंतान दंपती को बेचने के बदले मोटी रकम दिलाने का लालच दिया। महिला के इनकार करने पर उसे डराया-धमकाया गया। पीड़िता के अनुसार, 4 नवंबर 2026 को प्रसव के बाद उसे नवजात शिशु समेत दोबारा अहिल्या के घर ले जाया गया, जहां उसे बंधक बना लिया गया। आरोपियों ने कथित तौर पर धमकी दी कि प्रसव में हुए खर्च की भरपाई बच्चे को बेचकर की जाएगी। महिला की सहमति के बिना नवजात को बेचने का प्रयास भी किया गया।

मुफ्त इलाज का झांसा देकर रायपुर बुलाया

इस पूरे मामले का खुलासा ओडिशा की एक गर्भवती महिला की शिकायत के बाद हुआ। आरोप है कि महिला को मुफ्त प्रसव और उपचार का भरोसा दिलाकर रायपुर बुलाया गया था। यहां उसकी मुलाकात कृतिका साहू, गीतिका और अहिल्या नाम की महिलाओं से कराई गई। इसके बाद उसे गोगांव स्थित अहिल्या के घर में ठहराया गया।

प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा पहुंचीं जिपं अध्यक्ष

रायपुर, 27 नवम्बर। सिख धर्म के प्रथम गुरु एवं महान संत गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष बेमेतरा कल्पना योगेश तिवारी बेमेतरा स्थित गुरुद्वारा साहिब पहुंचीं। यहां उन्होंने श्रद्धापूर्वक मत्था टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया तथा गुरुद्वारा साहिब में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सिख समाज के सभी लोगों को प्रकाश पर्व की लख-लख बधाइयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह चावला सहित सिख समाज के सम्मानित पदाधिकारीगण, प्रबुद्धजन, माताएं-बहनें एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संत ज्ञानी द्वारा मधुर वाणी में प्रस्तुत किए जा रहे गुरुवाणी संकीर्तन ने उपस्थित संगत को भावविभोर कर दिया। गुरुवाणी के पावन शब्दों और भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में पूरा गुरुद्वारा साहिब श्रद्धा एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। इस अवसर पर कल्पना योगेश तिवारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज को प्रेम, सेवा, समानता, सत्य और भाईचारे का मार्ग दिखाने वाला पावन अवसर है।



5,000 युवाओं को साइबर सुरक्षा और एआई में प्रशिक्षित करने एमओयू

रायपुर, 27 नवम्बर। एनआईआईटी फाउंडेशन ने रायपुर जिला प्रशासन के साथ एक साझेदारी की है। इसके तहत 5, 000 छात्रों को साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाएगा। युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने के प्रयासों के तहत एनआईआईटी फाउन्डेशन ने यह पहल की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई की मौजूदगी में एमओयू एक्सचेंज किया गया। यह पहल साइबर सुरक्षा प्लस के माध्यम से लागू की जाएगी, साइबर एंड एआई वर्कफोर्स प्रोग्राम और साइबरस्मार्ट एआई प्राइम इस पहल के मुख्य अवयव होंगे। इस प्रोग्राम में रायपुर जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित विभिन्न संस्थानों और केंद्रों के छात्र शामिल होंगे। यह प्रोग्राम एमओयू साईन किए जाने की तारीख से एक साल तक जारी रहेगा।



इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नई तकनीकों और सुरक्षित डिजिटल तौर-तरीकों का व्यावहारिक ज्ञान देना है, साथ ही शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता से जुड़ी क्षमताओं को विकसित करना है। इस अवसर पर एनआईआईटी फाउंडेशन की कंट्री डायरेक्टर, डॉ. चारू कपूर ने कहा, साइबर सुरक्षा प्लस के माध्यम से, हमारा लक्ष्य युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। साथ ही हम ही जिम्मेदार और सुरक्षित डिजिटल तौर-तरीकों को भी बढ़ावा देना चाहते हैं।''

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के साथ यह साझेदारी युवाओं को ऐसे कौशल और जागरूकता विकसित करने में मदद करेगी, जिससे वे पूरे आत्मविश्वास के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सकें। रायपुर के जिला कौशल विकास प्राधिकरण के सहायक निदेशक, शरत चंद्र शुक्ला ने कहा कि युवाओं में डिजिटल क्षमताएं विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के लिए तैयार किया जा सके।

उन्होंने कहा, साइबर सुरक्षा प्लस के जरिए एनआईआईटी फाउंडेशन के साथ यह साझेदारी युवाओं को साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूक बनाने में मदद करेगी। साथ ही, यह डिजिटल रूप से सशक्त और भविष्य के लिए तैयार रायपुर के हमारे विजन को साकार करने में भी योगदान देगी। सिस्को की पहल साइबर सुरक्षा प्लस का उद्देश्य तकनीक, शिक्षा और सामुदायिक जुड़ाव को एक साथ लाकर युवाओं साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक बनाना है। यह प्रोग्राम छात्रों को नई तकनीकों को समझने, सुरक्षित डिजिटल तौर-तरीकों को अपनाने और तकनीक-उन्मुख माहौल में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेगा। यह साझेदारी ऐसे समय में की गई है जब डिजिटल तकनीकें शिक्षा, रोज़गार और रोज़मर्रा के कामों का अहम हिस्सा बनती जा रही हैं, ऐसे में युवाओं साइबर सुरक्षा के बारे में जागरुक और डिजिटल रूप से साक्षर बनाना और भी ज़रूरी हो गया है।



कौशल किशोर मिश्र प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी की ओर से तरुण छत्तीसगढ़, तरुण छत्तीसगढ़ प्रेस टॉवर, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं प्रकाशित प्रधान संपादक- कौशल किशोर मिश्र, पंजी. क्रं. 45088/85 डाक पं.छ.ग./रायपुर संभाग/33/2024-26